छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 65 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 28 फरवरी 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

कैशियर का फर्जी पदमुद्रा तैयार करके 01 करोड़ 07 लाख से अधिक डकारा, केस दर्ज

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में पदस्थ लिपिक का कारनामा

कोतवाली थाना पुलिस ने दर्ज किया प्राथमिकी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 प्रभारी के द्वारा किए गए एक करोड़ 07 लाख 84 हजार 340 रुपये गबन के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके पहले जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई करते हुए इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय मैनपाट नियत किया था।

उपसंचालक के पद पर पदस्थ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने कोतवाली थाना पुलिस को दिए गए पत्र में बताया है कि फुंदुरडिहारी निवासी प्रदीप कुमार अम्बष्ट सहायक ग्रेड 02, प्रभारी लेखा शाखा कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में सेवा पुस्तिका के अनुसार 30.03.1990 से निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ थे। वर्ष 2013 में शिव बहादुर यादव के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 2013 से प्रदीप कुमार अम्बष्ट को कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में लेखा शाखा का प्रभार दिया गया। इन पर स्वयं से कैशियर, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं का पदमुद्रा तैयार करने का आरोप भी लगा है, जबकि कैशियर का कोई पद

कार्यालय में सृजित नहीं है। कार्यालय में सहायक ग्रेड-02 एवं 03 का पद है, जिन्हे लेखा शाखा का प्रभार दिया जाता है। बताया गया है कि प्रदीप कुमार अम्बष्ट विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजना बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण, सूकर त्रयी ईकाई वितरण एवं नर सूकर वितरण योजना की अंशदान राशि हितग्राहियों से प्राप्त होने पर अधिकारी-कर्मचारियों से प्राप्त करके कथित रूप से जमा था और अपनी बनाई गई पदमुद्रा से पावती देता था। पावती में इनके द्वारा राशि प्राप्त कर सीजीटीसी/एमपीटीसी जारी कर दिया जाता था। नियमानुसार उक्त राशि को आहरण संवितरण अधिकारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के द्वारा बैंक खाते में जमा करना आवश्यक है एवं शासकीय दस्तावेज में भी इंद्राज करना है। सीजीटीसी/एमपीटीसी बुक शासकीय मुद्रणालय राजनांदगाव से चालान जमा करने पर कार्यालय को प्राप्त होती है, जो कि शासकीय राजस्व जमा करने वाले को जारी की जाती है। इसी प्रकार जिला पशु रोगी कल्याण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जिले में संचालित समस्त संस्थाओं से एकत्रित कर समिति के बैंक खाते में जमा की जाती है। जिले के समस्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क नियमानुसार कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में प्रदीप कुमार अम्बष्ट सहायक ग्रेड 02 प्रभारी लेखा शाखा के पास जमा की जाती थी, इसके बाद उनके द्वारा स्वयं से बनवाए गए पद मुद्रा का उपयोग करके जमा करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को शासकीय रसीद प्रदाय कर दी गई, परंतु प्राप्त राशि जिला पशु रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

आहरण संवितरण अधिकारी ने किया जांच समिति का गठन

इसी क्रम में आहरण संवितरण अधिकारी डॉ. आर.पी. शुक्ला, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर के समक्ष अनादेश क्रमांक 143293, 01 लाख 21 हजार 471 रुपये हस्ताक्षर हेतु प्रदीप कुमार अम्बष्ट प्रभारी लेखा शाखा द्वारा सीजीटीसी से प्राप्त राशि, बैकयार्ड परिवहन में व्यय करने हेतु प्रस्तुत किया गया। डॉ. शुक्ला ने संबंधित मद में उपलब्ध राशि की जानकारी प्रदीप कुमार अम्बष्ट से चाही थी, परंतु उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.07.2025 के द्वारा संबंधित मद में सीजीटीसी/एमपीटीसी की विविध राशि के मिलान हेतु एक समिति का गठन किया गया। इसमें डॉ. अरुण कुमार सिंह अतिरिक्त उप संचालक, डॉ. फ्रैंकलिन टोप्पो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉ. नंदलाल यादव, अमित कुमार वर्मा एवं उमेश कुशवाहा, द्वय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को शामिल किया गया था। समिति को 5 दिवस के भीतर आहरण संवितरण अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन सौंपने हेतु निर्देशित किया गया था।

दस्तावेज और जमा राशि का विवरण नहीं दिया लिपिक

जिला पशु कल्याण समिति के जमा राशि के सत्यापन हेतु गठित समिति ने पत्र दिनांक 28.07.2025 द्वारा विविध योजना अंतर्गत कार्यालय में जमा अंशदान राशि एवं जिला पशु रोगी कल्याण समिति की जमा राशि की सीजीटीसी/एमपीटीसी एवं रसीद के सत्यापन हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराने कहा गया। इधर प्रदीप कुमार अम्बष्ट ने सीजीटीसी एवं जिला पशु कल्याण समिति की राशि को आहरण संवितरण अधिकारी के बैंक खाते में जमा करने का विवरण नहीं दिया। समिति द्वारा इन्हें 14 दिवस के भीतर अपना लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया और लेखा शाखा द्वारा जारी सीजीटीसी/एमपीटीसी एवं पशु रोगी कल्याण समिति में जारी रसीद के अनुसार प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा करने का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में शासकीय राशि की वसूली के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, सामान्य शाखा गृह विभाग को सौंपने हेतु लेख किया है।

लिपिक ने दी संवैधानिक कार्रवाई करने की धमकी

प्रतिवाद में प्रदीप कुमार अम्बष्ट द्वारा कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर के लेटर हेड का उपयोग करते हुए समिति को उल्लेख किया गया कि आहरण संवितरण अधिकारी का दस्तावेज, आहरण समिति वितरण अधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। इधर जांच टीम का तर्क है कि यह दस्तावेज आहरण संवितरण अधिकारी का ही होता है, इसे देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रदीप कुमार अम्बष्ट द्वारा एक तरफ शासकीय राशि का गबन, दूसरी तरफ कार्यालयीन लेटर हेड का गलत उपयोग करने को दंडनीय अपराध मानते हुए संदेह की पुष्टि करने कार्यालयीन पत्र दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से प्रदीप कुमार अम्बष्ट से विगत 10 वर्षों में सीजीटीसी/एमपीटीसी जारी कर प्राप्त राशि का शासकीय खाते में जमा एवं व्यय का विवरण मांगा गया। इस जानकारी को भी देने से उन्होंने कार्यालयीन लेटर हेड का उपयोग करते हुए मना कर दिया। आरोप है कि विवरण मांगने पर संवैधानिक कार्रवाई करने की धमकी दी गई।

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला

विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक राशि रुपये 44 लाख 54 हजार 700 रुपये एवं जिला पशु रोगी कल्याण समिति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 63 लाख 29 हजार 640 रुपये, कुल एक करोड 07 लाख 84 हजार 340 रुपये प्रदीप कुमार अम्बष्ट के द्वारा जिले के विभिन्न पशु चिकित्सीय संस्थाओं से प्राप्त करने उपरांत शासकीय बैंक खाते में जमा नहीं करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 316 (4) का मामला दर्ज किया है। बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न योजनाओं की राशि उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के शासकीय बैंक खाता में जमा नहीं की गई है।

आईएएस कुलदीप शर्मा बलौदाबाजार कलेक्टर, 11 अफसरों को सरकार ने दी नई जिम्मेदारियां

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। इसके साथ ही कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. सीआर प्रसन्ना (2006 बैच), सचिव सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं कुलदीप शर्मा (2014 बैच), रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं को अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पद पर पदस्थ किया गया है।

तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बनाया गया है, साथ ही उन्हें धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

लीना कोसम को परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर पद पर यथावत रखा गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2016 के तहत वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है।

इसी प्रकार सौमिल रंजन चौबे (उप सचिव, कृषि विभाग), बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई (अपर कलेक्टर, नारायणपुर), सुमीत अग्रवाल (आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग) और संदीप कुमार अग्रवाल (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर) को यथावत पदस्थ किया गया है।

आशीष कुमार टिकरिहा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन नियुक्त किया गया है, जिसे वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष दर्जा दिया गया है। वहीं ऋषभ कुमार पाराशर (उप सचिव, वित्त) यथावत रहेंगे तथा तरूण कुमार किरण को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय कोरबा पदस्थ किया गया है।

मेडिकल कॉलेज और नवापारा अस्पताल में स्वास्थ्य जांच का अभाव

आर्थिक रूप से कमजोर लोग दुविधा में, शिविर लगाकर निःशुल्क इलाज कराने की मांग

एआईसीसी सदस्य के साथ कांग्रेसजन खटिकपारा व झंझटपारा में घर-घर दस्तक दिए

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। दूषित पेयजल सप्लाई के कारण कई घरों में लोगों के जलजनित रोगों से ग्रसित होने की शिकायत उपरांत शुक्रवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने नमनाकला के खटिकपारा एवं झंझटपारा में घर-घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। लम्बे समय से दूषित जल की सप्लाई एवं साफ-सफाई के अभाव में क्षेत्र में पीलिया, टायफाइड और डायरिया की बीमारी के फैलाव की जानकारी सामने आ रही थी।

क्षेत्र का दौरा करने के उपरांत आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने जानकारी दी कि लगभग प्रत्येक घर में एक या एक से अधिक सदस्य बीमारियों के शिकार हैं। प्रत्येक घर से मिले इलाज से संबंधित पर्चियों से इस बात की जानकारी मिली है कि लोग पीलिया, टायफाइड और डायरिया से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने यह बताया है कि इस क्षेत्र से 2 लोगों के मौत की चर्चा सामने आने के बाद विगत दो-तीन दिनों से पेयजल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सिंहदेव ने कहा कि नावापारा स्वास्थ्य केन्द्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के अभाव में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को इलाज में भी कठिनाईयां आ रही हैं। बीमार लोगों ने यह भी शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें बाहर से जांच कराने में हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर काफी व्यय हो रहा है। आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में मेडिकल शिविर लगाकर बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धन्जल, आलोक सिंह, प्रमोद चौधरी, तीरथ चौधरी, चंद्रप्रकाश सिंह, अमित सिंह मौजूद थे।

खराब पानी पीने से होती है ये बीमारियां

बीमार लोगों के पर्चियों का अवलोकन के उपरांत पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की ने कहा कि क्षेत्र कें सभी बीमारों की बीमारी जलजनित है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीलिया, टायफाइड और डायरिया जैसी बीमारी है जो कि खराब पानी पीने के कारण होती है। उन्होंने निगम प्रशासन का सलाह दिया है कि ऐसी परिस्थिति में गलत बयानबाजी कर तथ्यों को छिपाने से बेहतर होगा कि मिल-जुलकर आमजन को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यही एक लोक सेवक का उत्तरदायित्व है।

फरियाद महापौर को लगता है साजिश

निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि आमजन के द्वारा दूषित पेयजल और बीमारी की फरियाद करना महापौर को साजिश लगता है, यह दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि पहले नवागढ़, मोमिनपुरा, पर्राडांड और अब नमनाकला क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई का तथ्य आना और इससे बीमारियों का फैलाव स्पष्ट करता है कि शहर के बड़े हिस्से में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि फिल्टर प्लांट में ही पेयजल का सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा हो। पेयजल की खराब गुणवत्ता का वाजिब कारण क्या है इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की मांग हमारे द्वारा की गई है। इस दिशा में पहल नहीं हुई तो कांग्रेस आमजन के स्वास्थ्य के हित में गंभीर आंदोलन के लिए सड़क पर आएगी।

लैलूंगा से गांजा लेकर पहुंचे 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गांजा तस्करी के मामले में साइबर सेल और रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 04 किलो गांजा और घटना में प्रयुक्त आई 20 कार, 06 मोबाइल फोन पुलिस ने जप्त किया है। आरोपी लैलूंगा से गांजा स्थानीय स्तर पर बिक्री करने के लिए लाए थे।

जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को पुलिस चौकी रघुनाथपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की आई 20 कार क्रमांक सीजी 10 एएल 8571 में तीन व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर लैलूंगा तरफ से आ रहे हैं और गंगापुर में मुरारी लाल चौबे को बिक्री करेंगे। सूचना पर पुलिस टीम संदिग्ध वाहन एवं संदेहियों को तलाशते गंगापुर मेन रोड में एनएच 43 के किनारे खेत के पास पहुंची, यहां कार के पास 04 व्यक्ति कुछ सामानों का लेन-देन करते दिखाई दिए। इन्हें घेराबंदी करके पुलिस पकड़ी। कार से आए सवार हेमसागर यादव

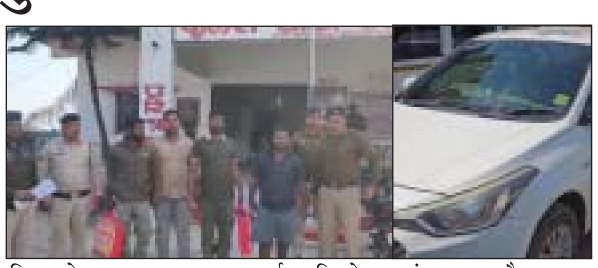

पिता पोरना राम यादव 26 वर्ष निवासी ग्राम नारायणपुर, मुड़ापारा थाना लैलुंगा जिला रायगढ़, खीरो यादव पिता सुशील यादव 25 वर्ष निवासी जोरोडाझरिया, चौकी कोलेनझरिया, थाना तुमला जिला जशपुर, भूपेन्द्र यादव पिता लोचन यादव 24 वर्ष निवासी पोतरा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ थे, वाहन के पास काले रंग का बैग लेकर मुरारी लाल चौबे पिता तिरथ राज चौबे 35 वर्ष खड़ा था, जो ग्राम गंगापुर, चौकी रघुनाथपुर थाना लुण्ड्रा का निवासी है। पुलिस टीम ने संदेह पर कार को चेक किया तो डिक्की में 02 किलोग्राम गांजा मिला, वाहन के पास काले रंग का बैग लेकर खड़े व्यक्ति मुरारी लाल चौबे के बैग में भी 02 किलोग्राम गांजा मिला। पुलिस टीम ने आरोपियों से 04 किलोग्राम गांजा, कार और 06 नग मोबाइल फोन जब्त किया है। गांजा की कीमत 36,000 रुपये और जब्त कार व मोबाइल कीमत 4 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक आर.एन. पटेल, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह व चंद्रभूषण तिवारी, आरक्षक जितेश साहू, मनीष सिंह, उमाशंकर साहू, अमन पुरी, विकास मिश्रा, उमेश खुटिया, इजहार अहमद, इदरीश खान, इजहार अहमद, संजीव चौबे सक्रिय रहे।

प्रेमिका के साथ पकड़ा गया फॉरेस्ट गार्ड, युवकों ने जमकर पीटा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सूरजपुर जिले में एक फॉरेस्ट गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंच गए और फॉरेस्ट गार्ड से मारपीट करने लगे। युवकों ने मोबाइल पर गाना बजाकर फॉरेस्ट गार्ड से डांस करवाया उसके बाद गर्लफ्रेंड के सामने उसकी पिटाई की।

मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो दो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

देवनगर बीट में पदस्थ है फॉरेस्ट गार्ड

जानकारी के अनुसार, फॉरेस्ट गार्ड का नाम सुखदेव पैकरा बताया गया है। वह देवनगर बीट में पोस्टेड है। फॉरेस्ट गार्ड देवनगर नर्सरी में अपनी प्रेमिका के साथ बैठा था इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंच गए और उसके साथ अभद्रता करने लगे।

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव पैकरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देवनगर नर्सरी घूमने आया था। जहां कुछ युवकों ने उसे देख लिया। इसके बाद युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसके फोन में गाना बजाया और फॉरेस्ट गार्ड से जमकर ठुमके लगवाए। जब फॉरेस्ट गार्ड ठीक से डांस नहीं कर पाया तो वह उसकी पिटाई करने लगे। युवकों ने गर्लफ्रेंड के सामने ही सुखदेव को डंडे और बेल्ट से

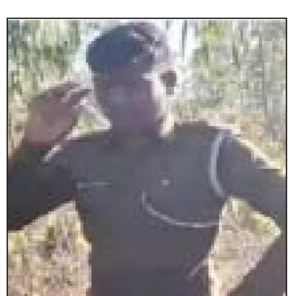

पीटा। पिटाई के दौरान फॉरेस्ट गार्ड यूनिफॉर्म में था। इस दौरान फॉरेस्ट गार्ड खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागता रहा और लोग उसकी पिटाई करते रहे।

मारपीट के बाद युवकों ने उसकी गर्लफ्रेंड को घर भेज दिया गया। जिस दौरान फॉरेस्ट गार्ड की पिटाई हो रही थी उस दौरान गर्लफ्रेंड चुपचाप खड़ी रही। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड की पिटाई की है वह लड़की के रिश्तेदार हैं।

डीएफओ ने भेजा नोटिस

फॉरेस्ट गार्ड के पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ ने मामले में संज्ञान लिया है। डीएफओ डीपी साहू ने फॉरेस्ट गार्ड को नोटिस जारी किया है। नोटिस में फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव पैकरा से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में लिखा है कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

> सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हमारी संज्ञान में आया है। फिलहाल, इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
>
> **प्रशांत कुमार ठाकुर**
> **एसएसपी, सूरजपुर**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार को ललकारा, सौंपा ज्ञापन

तीन सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर 09 मार्च को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान करने की मांग को लेकर दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन के क्रम में दूसरे दिन धरनास्थल से रैली निकाली और तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की केन्द्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर 26 व 27 फरवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और आंगनबाड़ियों को बंद करते हुए जिला मुख्यालय में धरना दिया था। नारेबाजी करते हुए निकाली गई रैली में इन्होंने सरकार और विभागीय मंत्रियों को ललकारा। अंत में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले एकजुट हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा देश में आइसीडीएस की स्थापना का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से शासन द्वारा कई प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, इसके बदले कार्यकर्ता को मात्र 4500 रुपये व सहायिका को 2250 रुपये प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों से मानदेय में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष पहले तो अपना घर चलाने की चिंता रहती है, बाद में बुढ़ापे की लाठी पेंशन नहीं मिलने का भय सताता है। सरकार से इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कार्यकर्ता को प्रतिमाह 26000 रुपये एवं सहायिका को 22100 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। इसके अलावा प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोत्तरी भी की जाए। साथ ही समाजिक सुरक्षा के रूप में सेवानिवृत्ति और आकस्मिक मृत्यु पर एकमुस्त ग्रेच्युटी, मासिक पेंशन और समूह बीमा का लाभ दिया जाए। इसके लिए नीति बनाई जाए। 8 मार्च तक मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 09 मार्च 2026 को रायपुर में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संयुक्त मंच के अलावा अन्य संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फरहान ने रखा पहला रोजा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नगर के मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद सलीम खान राही और महजबी खान के पुत्र मोहम्मद फरहान खान ने अपना पहला रोजा मुकम्मल किया। फरहान ने बताया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने रोजा रखा और बिना खाना खाए और पानी पिए अपना पहला रोजा मुकम्मल किया, और अल्लाह से देश में और दुनिया में अमन, चैन और शान्ति बनी रहे, साथ ही अपने और अपने दोस्तों की अच्छी सेहत के लिए दुआ की। मोहम्मद फरहान खान होलीक्रॉस स्कूल में यू.के.जी. ए के छात्र हैं, इन्हें पहला रोजा रखने पर दादी सलमा खातून, नानी हाशमा जबी, नाना अब्दुल हमीद सहित सभी लोगों ने बधाईयां दी।

ब्वाय हॉस्टल के बाथरूम से नल निकालकर ले गए चोर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय गंगापुर के ब्वाय हॉस्टल के बाथरूम से स्टील का कीमती नल चोरी करके ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। सुरक्षा प्रभारी ने घटना की जानकारी गांधीनगर थाने में दी है, जिस पर पुलिस अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के कृष्ण कुमार जिला संयोजक नियुक्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व सहसंयोजक की घोषणा कर दी गई है। जिसमें नगर पंचायत शिवनंदनपुर निवासी कृष्ण कुमार गोयल बल्लू को संगठन का सुरजपुर जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। उक्त नियुक्ति से संगठन कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। नवनियुक्त जिला संयोजक कृष्ण कुमार गोयल ने कहा है कि संगठन द्वारा मुझे जिस उम्मीद से उक्त जिम्मेदारी सौंपी गई, उस पर मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करूंगा।

जनगणना 2027 : प्रथम चरण के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ

मकान, जनसंख्या गणना एवं सूचीकरण के कार्यों के लिए अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

जिसमें आज प्रथम दिवस प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, मकान गणना एवं आगामी जनसंख्या गणना के कार्यों को सुव्यवस्थित, सटीक एवं समयबद्ध रूप से संपादित करने हेतु अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों का उपयोग देश के विकास व जनकल्याण हेतु नीति और कार्यक्रम बनाने में किया जाता है। कलेक्टर ने आंकड़ों की शुद्धता और सटीकता पर विशेष जोर देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी

गंभीरता, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ करने को कहा, ताकि सही और विश्वसनीय आंकड़े मिल सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना निदेशालय के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर संयुक्त निदेशक श्री दीपक गोदे तथा जनगणना नोडल अधिकारी श्री बैद्यनाथ कुमार एवं मोहित तिवारी ने प्रथम चरण में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से मकान सूचीकरण की प्रक्रिया, मकानों के प्रकार, डिजिटल फॉर्म भरने की विधि, फील्ड में डेटा एकत्र करने का तरीका और जनगणना के लिए तैयार सीएमएमएस पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। प्रशिक्षकों ने फील्ड में आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की। प्रशिक्षण में अधिकारियों को यह भी बताया गया कि डाटा की जांच कैसे की जाए और लोगों को डिजिटल स्व-गणना के लिए किस तरह सही मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगतियों से बचा जा सकें। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री आर.एन. पाण्डेय, श्री अभिषेक गुप्ता, जिला सांख्यिकी अधिकारी श्री संतोष श्रीवास्तव, सभी चार्ज अधिकारी (ग्रामीण एवं नगरीय), सर्व जनगणना लिपिक (ग्रामीण एवं नगरीय) भी उपस्थित रहे।

मेमू ट्रेन का इंजन फेल, दो घंटे जंगल में फंसे रहे यात्री

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-अनूपपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन के लगातार विलंब से परिचालन को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को ट्रेन संख्या 68758 का इंजन बीच रास्ते फेल होने से सैकड़ों यात्री करीब दो घंटे तक जंगल क्षेत्र में फंसे रहे। बाद में ट्रेन को कोतमा तक लाकर रद्द कर दिया गया। शुक्रवार को भी उक्त मेमू ट्रेन निरस्त रही। गौरतलब है कि मेमू ट्रेन संख्या 68758 गुरुवार शाम 6.10 बजे अंबिकापुर से अनूपपुर के लिए रवाना हुई थी, जिसका निर्धारित आगमन समय रात 10 बजे अनूपपुर है। लेकिन बिजुरी और कोतमा के बीच भैयाटोला के पास अचानक पावर इंजन के पाइप में खराबी आ गई, जिससे ट्रेन बीच जंगल में रुक गई। करीब दो घंटे बाद दूसरे इंजन की व्यवस्था कर ट्रेन को कोतमा तक लाया गया, जहां से उसे रद्द कर दिया गया। अचानक ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन में सवार बिश्रामपुर निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि वे अपनी पुत्री श्रेया को बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा दिलाने भोपाल ले जा रहे थे। उन्हें अनूपपुर से अमरकंटक एक्सप्रेस पकड़नी थी, लेकिन मेमू ट्रेन की देरी के कारण वे समय पर अनूपपुर नहीं पहुंच सके। कोतमा में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेन रद्द कर दी गई, जिससे उनकी पुत्री की परीक्षा छूट गई। यात्रियों का कहना है कि अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू अक्सर विलंब से चलती है, जिससे कनेक्टिंग ट्रेनें छूट जाती हैं और आगे की यात्रा प्रभावित होती है। लगातार लेटलतीफी और अब तकनीकी खराबी के कारण लोग मेमू ट्रेन की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। यात्रियों ने आरोप लगाया कि रेल प्रबंधन मालगाड़ियों को प्राथमिकता देता है, जबकि यात्री ट्रेनों को बीच रास्ते खड़ा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन की ओर से शुक्रवार को भी मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई थी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी।

कृषक उन्नति योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री करेंगे आदान सहायता राशि जारी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत एवं धान बीज उत्पादक किसानों को 28 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा 10,324 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। यह राशि डीबीटी माध्यम से पारदर्शी तरीके से किसानों को प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रमों में संबंधित विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होंगे। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन एवं उप संचालक कृषि विभाग के नेतृत्व में सभी विकासखण्डों में 28 फरवरी 2026 को प्रातः 11:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसके अंतर्गत विकासखण्ड बलरामपुर में बाजारपारा स्थित ऑडिटोरियम भवन, विकासखण्ड रामचन्द्रपुर में (रामानुजगंज) जनपद पंचायत सभाकक्ष, विकासखण्ड वाड्रफनगर में सहकारी समिति विरेन्द्रनगर, विकासखण्ड राजपुर में जनपद पंचायत सभाकक्ष, विकासखण्ड शंकरगढ़ में जनपद पंचायत सभाकक्ष, विकासखण्ड कुसमी में जनपद पंचायत सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उप संचालक कृषि श्री रामचन्द्र भगत ने जिले के सभी पात्र कृषकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर अपने निकटतम कार्यक्रम होकर शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।

बीमारी से तंग आकर वृद्ध ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक वृद्ध ने आज घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

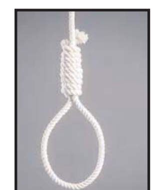

जयनगर पुलिस ने ग्राम पंचायत सिलफिली यादवपारा निवासी 60 वर्षीय सुखदेव यादव पिता हरिनंदन यादव पिछले 8-10 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। परिजन ने बताया कि वृद्ध ने बीमारी से तंग आकर शुक्रवार की सुबह घर में अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

जेएमक्यू कालोनी में पीलिया बीमारी से एक युवक की मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर के जेएमक्यू निवासी सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मी भागीरथी भारती के 37 वर्षीय पुत्र जितेंद्र भारती की पीलिया बीमारी की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दस दिनों पूर्व उन्हें पीलिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी के बाद परिजन उन्हें घर ले आए फिर उनकी तबियत बिगड़ गई। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान

उसकी मौत हो गई। गुरुवार को स्थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। जितेंद्र अपने पीछे दो बेटी, पत्नी, मां पिता भाई सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। जितेंद्र भारती रेलवे स्टेशन स्थित शगुन श्रृंगारिका के संचालक सत्येंद्र उर्फ बाबू के ज्येष्ठ भ्राता थे।

सब्सिडी से सोलर पैंनल लगाना हुआ आसान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए लोगों में लगातार रूझान बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जिले के राजपुर विकासखंड के चरगढ़ निवासी श्री भूखनारायण सिंह का घर जगमग हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से प्रभावित होकर श्री सिंह ने अपने घर में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया है। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो गया है। उन्होंने बताया कि घर में बिजली के उपयोग के आधार पर पहले प्रतिमाह हजारो रूपए बिजली का बिल आता था। जो की अब कम हो गया है। उन्होंने बताया कि रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने में लगभग 2 लाख रुपए की लागत आयी है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपए तथा राज्य शासन द्वारा 30 हजार रुपए की सब्सिडी मिली है। इस प्रकार कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी मिली है। शेष राशि के लिए बैंक फाइनेंस की सुविधा मिली है। बैंक फाइनेंस बहुत ही आसान किस्तों में हुआ है।

श्री भूखनारायण सिंह प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से बार-बार बिजली बंद होने की समस्या से निजात मिली है। जिसके लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

पहाड़गांव से एनएच 43 तक बनेगी नई सड़क, विकास को मिलेगी रफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अधोसंरचना विकास को नई दिशा देते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयास से पहाड़गांव से गोपालपुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक पहुंच मार्ग निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल है, जिसके तहत 5.10 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण पुल-पुलिया सहित किया जाएगा। यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों के लिए जीवनरेखा साबित होगा और ग्रामीण अंचलों को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलती है। जब गांव शहरों और मुख्य मार्गों से जुड़ते हैं, तो अवसरों के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि नई

सड़क बनने से किसानों को अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। बरसात के मौसम में कीचड़ और जर्जर रास्तों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह मार्ग संजीवनी साबित होगा, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सड़क बनने के बाद छोटे व्यवसाय, परिवहन सेवाएं और अन्य आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दोहराया कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। चरणबद्ध तरीके से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे।

रामनगर में श्री कृष्ण गोवर्धन कराह पूजा का आयोजन 6 मार्च को

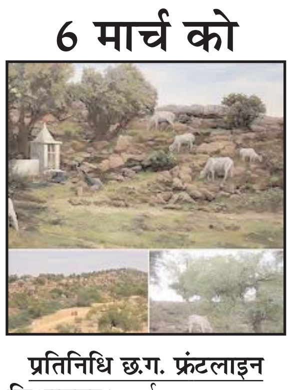

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। सर्व यादव समाज के तत्वावधान में ग्राम पंचायत रामनगर के शक्ति चौक झिरगिमुड़ा में शुक्रवार 6 मार्च को अमर देव बाबा श्री कृष्ण गोवर्धन (कराह) पूजा का आयोजन किया गया है। सर्व यादव समाज के बाबूलाल यादव ने कराह पूजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सहभागी बनकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है।

पीएम जनमन योजना से पीवीटीजी बस्तियों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से घर के समीप जांच एवं उपचार सुविधा

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। दूरस्थ वनांचल और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

जिले में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। इन यूनिटों के माध्यम से विकासखण्ड बलरामपुर, राजपुर, कुसमी और शंकरगढ़ के सुदूर पहाड़ी कोरवा बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सीधे गांव और बसाहटों तक पहुंचाई जा रही हैं। अब ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए, कई किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्रों की ओर नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं उनके घर के समीप पहुंच रही हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ रक्तचाप, शुगर, हीमोग्लोबिन जैसे आवश्यक लैब टेस्ट किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर मरीजों को आगे के उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर भी किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा बुजुर्गों की देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 235 बसाहटों में 87 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में कुल 3,678 हितग्राहियों को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। पहले जहां ग्रामीण सामान्य बुखार या संक्रमण को नजरअंदाज कर देते थे या बैगा गुनिया का सहारा लेते थे, लेकिन अब वे नियमित जांच और परामर्श के महत्व को समझने लगे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

गौरतलब है कि जिले में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में मोबाइल मेडिकल यूनिट का सुव्यवस्थित संचालन किया जा रहा है। नियमित मॉनिटरिंग, तय रूट चार्ट और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बसाहटों में स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित की जा रही है। पीएम जनमन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार निश्चित ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में सशक्त प्रयास सिद्ध हो रहा है।

बहुआयामी व्यवसाय से रेबेका का संवरा जीवन, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बनीं लखपति दीदी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत चिलमा निवासी श्रीमती रेबेका महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़कर लाखों रुपए वार्षिक आय के रूप में अर्जित कर रही हैं।

वे बताती है कि कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा उनका परिवार मजदूरी कर जीवनयापन करता था। सीमित आय के कारण घर की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता था। परिस्थितियों से हार मानने के बजाय रेबेका ने स्वयं शक्ति महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर नया रास्ता चुना। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत स्वयं शक्ति महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। समूह के

माध्यम से उन्हें बचत, ऋण एवं स्वरोजगार की जानकारी मिली। उन्होंने समूह से ऋण लेकर बागबानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, किराना दुकान एवं कृषि कार्य को व्यवसाय के रूप में शुरू किया। आज वे मेहनत कर लगभग 1 लाख 71 हजार रुपये की सालाना आय अर्जित कर रही है। आय में वृद्धि से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है जिससे बच्चों की शिक्षा, पोषण और घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी बेहतर ढंग से कर रही है और लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। रेबेका के प्रयास से उनकी आमदनी बढ़ी है साथ ही परिवार का जीवन स्तर भी सुधरा है। रेबेका बताती हैं कि बिहान से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। जिससे वे आत्मनिर्भता की राह पर अग्रसर हुई हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी समूह से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। पशुपालकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं सहकारी समितियों के माध्यम से पशु औषधि विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

योजना के तहत पात्र प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियां अपने क्षेत्र में पशु औषधि विक्रय केंद्र स्थापित कर सकेंगी। इसके लिए न्यूनतम 120 वर्ग फुट स्थान (स्वयं का या किराए पर) होना अनिवार्य है। साथ ही केंद्र संचालन के लिए बी-फार्मा एवं डी-फार्मा डिग्रीधारी की नियुक्ति और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से औषधि विक्रय लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों के लिए शुल्क में छूट प्रदान की गई है। प्रत्येक विकासखंड में केवल एक ही पशु औषधि विक्रय केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश शासन के स्तर पर चयनित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियों को क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सालय भवन या परिसर में अनुबंध के आधार पर स्थल प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान की जा सकेगी। यह योजना Department of Pharmaceuticals, Ministry of Cooperation & Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India के सहयोग से संचालित की जा रही है। पशु औषधि केंद्र स्थापना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन www.dahd.gov.in लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रदर्शन/ शैक्षणिक वीडियो प्रतिदिन दोपहर 3:00 से 4:00 बजे के बीच विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इस योजना से पशुपालकों को बाजार दर से कम कीमत पर दवाइयाँ मिल सकेंगी, जिससे पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर ने विकासखण्ड बतौली का दौरा कर विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं का लिया जायजा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने शुक्रवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के साथ बतौली विकासखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सुविधाओं का आकलन करने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया।

करदना में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

कलेक्टर वसंत दौरे के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र करदना पहुंचे। उन्होंने यहां स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं संसाधनों एवं चिकित्सकीय उपकरणों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।विकासखंड में कार्यरत अधिकारी- कर्मचारियों का मुख्यालय में निवास करने एवं निर्धारित समय में उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करने निर्देशित किया।

पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम भटको का किया निरीक्षण

कलेक्टर वसंत ने पहाड़ी कोरवा कन्या आश्रम भटको का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से मिलकर सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने शयन कक्ष, आश्रम परिसर, किचन आदि का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को आश्रम में भोजन बनाने हेतु गैस कनेक्शन दिलवाने के निर्देश दिए।इस दौरान परिसर में निमार्णाधीन अतिरिक्त कक्ष का भी अवलोकन किया तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु निर्देशित किया।

निमार्णाधीन पीडीएस दुकान करदना का किया निरीक्षण

इस दौरान कलेक्टर ने निमार्णाधीन पीडीएस दुकान करदना का अवलोकन किया तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार राशन वितरण हो, हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस पर विशेष ध्यान रखें।

करदना में विद्यालयों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश

कलेक्टर ने हाईस्कूल करदना पहुंचकर बच्चों से मिले तथा शिक्षा गुणवत्ता पर फीडबैक लिया। उन्होंने प्रार्थना के समय बच्चों को 30 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिए। उन्होंने न्यूज डेस्क की व्यवस्था का भी अवलोकन किया तथा प्रतिदिन बच्चों को दो से तीन पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करवाने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़े और दिन-प्रतिदिन के समाचार के बारे में जानकारी रहे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का एक समाचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय करदना का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर वसंत ग्राम पंचायत भटको स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे। विद्यालय में बालिकाओं हेतु जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया तथा उनसे बात कर व्यवस्थाओं के बारे में पूछा।

शैक्षणिक भ्रमण पर विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर जाने वाले विद्यार्थियों को महापौर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला सरगुजा अजीत वसंत के मार्गदर्शन में समग्र शिक्षा (प्रारंभिक) जिला सरगुजा द्वारा राष्ट्रीय अविष्कार योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा एवं नवाचार क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु जिले के चयनित छात्र-छात्राओं का दल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के शैक्षणिक भ्रमण हेतु अंबिकापुर से प्रातः 9 बजे रवाना हुआ। शहर की प्रथम महिला महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों को शुभकामनाओं सहित प्रस्थान कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की यह दूरदर्शी एवं महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक वातावरण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। ऐसे शैक्षणिक भ्रमण बच्चों की सोच को सीमाओं से बाहर ले जाकर उन्हें विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अनुभव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं उज्ज्वल भविष्य निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस अंतरराज्यीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए जिले से पांच छात्र एवं पांच छात्राओं का चयन किया गया है, जो दूरस्थ एवं विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों से हैं तथा अपने-अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी हैं। विशेष रूप से मैनपाट क्षेत्र के माझी समुदाय के चार छात्र इस दल में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ये सभी विद्यार्थी मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्रों के निवासी हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की है।

आमगांव में किसानों को मिला मौसम आधारित खेती का मार्गदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। ग्रामीण कृषि मौसम परियोजना के अंतर्गत परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अम्बिकापुर द्वारा ग्राम आमगांव, विकासखंड सूरजपुर में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सह संचालक अनुसंधान डॉ. के. एल. पैंकरा के निर्देशन में किया गया। उन्होंने मौसम आधारित कृषि प्रबंधन एवं समेकित खेती पर मार्गदर्शन दिया। डॉ. पी. के. भगत ने कीट एवं रोग नियंत्रण के उपाय बताते हुए नीम आधारित कीटनाशक, लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप के उपयोग की सलाह दी। डॉ. आर.एस.सिदार ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में उद्यानिकी योजनाओं, जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए फसल आकस्मिक योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. रंजीत कुमार ने जीकेएमएस परियोजना, मौसम पूर्वानुमान एवं मेघदूत, मौसम, दामिनी ऐप के उपयोग के बारे में जानकारी दी। डॉ. आर. एस. सिदार एवं डॉ. सीताराम दुबौलिया ने जैविक खेती एवं उद्यानिकी के महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं डॉ. अरुणिमा त्रिपाठी ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के आधार पर फसल प्रबंधन की जानकारी दी। यमलेश निषाद एवं सुश्री शिवानी मिश्रा ने किसानों को मौसम संबंधी मोबाइल एप्लिकेशन की उपयोगिता और उनके प्रयोग की विधि को सरल तरीके से समझाया। कार्यक्रम में 65 से अधिक किसानों ने भाग लिया और मौसम जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साह दिखाया।

एनीमिया के रोकथाम एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों में एनीमिया बीमारी के रोकथाम हेतु 01 वर्ष से 19 वर्ष के किशोर (लड़के और लड़कियों) को जागरूकता एवं बचाव हेतु विकासखण्ड बतौली, लुण्ड्रा, सीतापुर एवं मैनपाट के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पी.एस. मार्को एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में बच्चों में एनीमिया के रोकथाम एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थान के शिक्षकों हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग से मास्टर ट्रेनर सिकल सेल नोडल डॉ. श्रीकांत सिंह चौहान के द्वारा प्राथमिक,माध्यमिक एवं हाई स्कूल के शिक्षक, व्याख्याता को एनीमिया 01 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के किशोर (लड़के और लड़कियों) में रोकथाम एवं जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने एनीमिया से रोकथाम संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आयरन से भरपूर आहार पालक, मेथी, सोयाबीन, अंडे, मांस और मछली का सेवन करें। उन्होंने बताया कि विटामिन सी नींबू, संतरा और आंवला जैसे फल खाएं, क्योंकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिरायु दल के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में शिविर का आयोजन किया जाता है, साप्ताहिक आयरन की गोली स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत दी जाने वाली नीली (किशोरों के लिए) या गुलाबी (बच्चों के लिए) आयरन की गोलियों के महत्व को बताएं। भ्रांतियों को दूर करें, बच्चों को समझाएं कि ये गोलियां सुरक्षित हैं और इन्हें खाली पेट नहीं, बल्कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए।

सनावल में जैविक खेती पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सनावल। यहाँ स्थित विज्ञान भवन में जैविक खेती विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर के अधिष्ठाता डॉ संतोष कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एवं डॉ नीलम चौकसे प्राध्यापक एवं कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा वित्तीय पोषित का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कृषकों और महिला समूहों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉ नीलम चौकसे ने कहा की हमें जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि हम उत्पादन के साथ-साथ अपने सेहत काफी ख्याल रख सकें। डॉ राजेश चौकसे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मेनपार्ट ने कहा के जब तक हम पशुओं का पालन नहीं करेंगे हम जैविक खेती की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। पशुओं के पालन से हमें प्रतिदिन लाभ तो हो सकता है और साथ ही जैविक खेती कर हम अपने मिट्टी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। डॉ रंजीत कुमार ने कहा कि जैविक खेती से जो लाभदायक कीट हमारे खेतों में उत्पनन होते हैं उससे मिट्टी भुरभुरी होती है एवं हानिकारक की संख्या में कमी आती है। डॉ वीरेंद्र चौहान ने विस्तार पूर्वक विभिन्न जैविक खाद्य पदार्थ एवं कीटनाशकों के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सनवाल एवं पचावल के सरपंच की गरिमामयी उपस्थिति रही, साथ ही क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पंकज चंद्राकर भी उपस्थित रहे। जहाँ उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से किसानों का मार्गदर्शन किए

किसानों को उपयोगी सामग्री का वितरण

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित किसानों को कृषि डायरी एवं कैलेंडर का वितरण किया गया, ताकि वे उन्नत खेती की तकनीकों से सतत जुड़े रहें। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर व्यावसायिक कृषि और उद्यमिता की ओर अग्रसर करना है।

मनीष यादव बने भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय के मार्गदर्शन में तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के निदेर्शानुसार, भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी एवं भाजयुमो जिला अध्यक्ष देव गुप्ता के सहमति से भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील साहू के मार्गदर्शन में अभिषेक गुप्ता ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसी क्रम में भैयाथान मंडल उपाध्यक्ष के रूप में मनीष यादव को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा होते ही क्षेत्र के युवा कार्यकताओं में उत्साह का माहौल देखा गया, और कार्यकताओं ने फोन वॉट्स सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दीं। नवनियुक्त मंडल उपाध्यक्ष मनीष यादव यादव ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें दी गई जिम्मेदारी का वे पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने युवा मोर्चा को अधिक सक्रिय, संगठित और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया।

मंत्री लक्ष्मी के प्रयासों से ग्रामीण संपर्क को नई रफ्तार, 5.10 किमी सड़क हेतु मिली स्वीकृति

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से जिले के ग्रामीण अंचलों को बड़ी सौगात मिली है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सड़क केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। मजबूत और सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलती है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि सूरजपुर जिला के पहाड़गांव से गोपालपुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग- 43 तक पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 5.10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पुल-पुलिया सहित किया जाएगा। यह सड़क क्षेत्र के अनेक ग्रामों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग के रूप में विकसित होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा और सुगम जुड़ाव सुनिश्चित होगा। इस सड़क निर्माण से आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनेगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक समय पर पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन में आसानी होगी। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

भुइरी बाई को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना से सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला रही हैं। जिले की हितग्राही भुइरी बाई पति कांशीराम कभी कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बने पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं।

कच्चे घर की तकलीफों से मिली मुक्ति

सरगुजा जिला के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंवरपुर की हितग्राही भुइरी बाई पति कांशीराम बताती हैं कि पहले वे कच्चे घर में रहती थीं, जहां हर मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश में पानी टपकता था, दीवारें कमजोर थीं और दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियां भी कठिन हो जाती थीं। ऐसे में पक्के घर का सपना उनके लिए बहुत बड़ा था, जो संसाधनों के अभाव में अधूरा ही लग रहा था।

संघर्ष के बीच पक्की छत का संबल

भुईरी बाई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उनके पति काशीराम के नाम स्वीकृत हुआ था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पक्का घर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, घर निर्माण के दौरान उनके पति का निधन हो गया, किंतु शासन की सहायता से बना यह पक्का आवास आज उनके जीवन का सहारा बना हुआ है। वे उसी घर में

सुरक्षित रूप से निवास कर रही हैं।

शासन की योजनाओं से बदली तस्वीर

भुइरी बाई ने बताया कि यदि शासन की आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तो वे कभी भी पक्का मकान नहीं बना पातीं। आज उन्हें न केवल मजबूत और सुरक्षित आवास मिला है, बल्कि अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उन्हें नियमित रूप से चावल, दाल एवं शक्कर मिल रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिलने से अब वे धुएं से मुक्त वातावरण में भोजन बनाती हैं, जिससे स्वास्थ्य और सुविधा दोनों में सुधार हुआ है।

सुशासन का जीवंत उदाहरण

भुईरी बाई भावुक होकर बताती हैं कि अब उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। पक्के घर में आराम और सुरक्षित जीवन जीना संभव हो पाया है। उन्होंने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन ने उनका पक्का मकान का सपना पूरा किया है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया है। सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

सम्पादकीय

उथल-पुथल के बीच नरेंद्र मोदी दिखाएंगे कूटनीतिक संतुलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल के दो दिनी दौरे पर पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब मध्य-पूर्व व पश्चिम एशिया में भारी उथल-पुथल है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान को घेरे हुए हैं और ईरान भी शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री की नौ साल में दूसरी इजरायल यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। देश में विपक्ष, खासकर कांग्रेस इस यात्रा को लेकर हमलावर है। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही भारत ने इजरायल और अरब देशों के साथ अपने संबंधों को रिसेट किया है। अब भारत की नीति हर देश के साथ द्विपक्षीय हितों और साझेदारियों पर केंद्रित है। हमारे फिलस्तीन और ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। भारत आतंकवाद से पीड़ित है और वह दुनिया में होने वाली ऐसी हर घटना के खिलाफ रहा है। भारत ने जहां इजरायल पर हमास के हमले का विरोध किया, वहीं वह गाजा में मानवीय सहायता को तेज करने का भी हिमायती रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा न तो किसी देश के खिलाफ है और न ही किसी के समर्थन में। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ ही साझा हितों को लेकर है। इस दो दिन की यात्रा में रक्षा और सुरक्षा, श्रम और व्यापार, एआई और प्रौद्योगिकी तथा आईएमईसी परियोजना के तहत कनेक्टिविटी एजेंडा में शीर्ष पर होंगे। इसके बावजूद मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच होने वाली बैठकों के परिणाम केवल द्विपक्षीय समझौतों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व और पश्चिम एशिया क्षेत्र को दिए जाने वाले संदेश भी इसमें शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान अधिकांश निर्धारित कार्यक्रमों में दोनों नेता साथ दिखाई देंगे। नेतन्याहू ने बुधवार को तेल अवीव हवाई अड्डे पर मोदी का खुद स्वागत किया और उन्हें यरुशलम की यात्रा पर ले गए। गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता और प्रेस वक्तव्यों के अलावा, वे निजी रात्रिभोज, एक नवाचार कार्यक्रम, यद वाशेम होलोकॉस्ट स्मारक संग्रहालय का दौरा और संभवतः इजराइल में बसे प्रवासी समुदाय से मुलाकात करेंगे, जिसे वहां बसे भारतीय-यहूदी समुदाय के साथ संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मोदी ने इजरायली संसद को भी संबोधित किया । इस यात्रा में मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले की धमकियों के बीच सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन साधना होगा, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है और प्रमुख ठिकानों से कर्मियों की वापसी हो रही है। हालांकि गुरुवार को ईरान-अमेरिका वार्ता के चलते इस सप्ताह हमले की संभावना कम दिखती है, फिर भी यह याद रखना चाहिए कि जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले वार्ता जारी रहने के बावजूद हुए थे। ईरान में भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह से जुड़े सवालों पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को कहा था कि यदि ईरान पर बमबारी होती है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, नई दिल्ली को उस कूटनीतिक छवि पर भी विचार करना होगा, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच तनाव के दौरान मोदी व नेतन्याहू साथ खड़े दिखाई देंगे। दोनों नेताओं के बीच वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण, प्रशासन और शांति स्थापना के लिए अमेरिका की "बोर्ड ऑफ पीस" योजना पर चर्चा चल रही है और भारत ने इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने का निर्णय लिया है।

प्रहार
कांतिलाल मांडोत

> 'प्रहार' केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की समग्र सोच का प्रतिबिंब है। इसमें सुरक्षा, तकनीक, सामाजिक जागरूकता, कानूनी संतुलन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समावेश है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समन्वय स्थापित हुआ और समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई तो निश्चित रूप से आतंकवाद की घटनाओं में और कमी लाई जा सकती है। यह नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को भटकाव से बचाने और राष्ट्र को स्थिर, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

आतंक के खिलाफ नई राष्ट्रीय ढाल

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति 'प्रहार' भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। आजादी के 78 वर्ष बाद एक समग्र, लिखित और स्पष्ट आतंकवाद विरोधी नीति का आना इस बात का संकेत है कि सरकार अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और पूर्व-निवारक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लंबे समय से सुरक्षा विशेषज्ञ यह सवाल उठाते रहे थे कि जिस देश ने दशकों तक सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद, अलगाववाद और वैश्विक आतंकी नेटवर्क की चुनौतियों का सामना किया है, उसके पास एक औपचारिक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति क्यों नहीं है।

अब 'प्रहार' के माध्यम से केंद्र ने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। इस नीति का मूल आधार 'जीरो टॉलरेंस' यानी आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या समुदाय से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इसे केवल राष्ट्र-विरोधी हिंसक कृत्य के रूप में देखा जाएगा। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद की चुनौती केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ी हुई है। जब नीति यह स्पष्ट करती है कि आतंकवाद किसी विशेष पहचान से संबद्ध नहीं है तो वह कट्टरपंथ की जड़ों को कमजोर करने की दिशा में भी काम करती है। 'प्रहार' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमले के बाद की कार्रवाई से अधिक हमले से पहले रोकथाम पर केंद्रित है। यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। पारंपरिक सुरक्षा मॉडल अक्सर किसी हमले के बाद जांच, गिरफ्तारी और दंड पर केंद्रित होते थे, लेकिन नई नीति में खुफिया तंत्र को सुदृढ़ कर संभावित हमलों को पहले ही विफल करने पर जोर दिया गया है। मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को तेज और प्रभावी बनाने का प्रयास इसी सोच का हिस्सा है। यदि विभिन्न एजेंसियों के पास मौजूद सूचनाएं समय रहते साझा हों और उन पर त्वरित कार्रवाई हो, तो कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। नीति में अल-कायदा और आइएसआइएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से खतरे का उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को केवल घरेलू संदर्भ में नहीं देख रहा, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी आकलन कर रहा है। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठन डिजिटल माध्यमों से युवाओं को प्रभावित करने और उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलने की रणनीति अपनाते रहे हैं। ऐसे में नीति का डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग पर ध्यान देना समय की मांग है। आज आतंकवाद केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं है; यह साइबर हमलों, ड्रोन तकनीक, फेक न्यूज और ऑनलाइन भर्ती के रूप में भी सामने आ रहा है। ड्रोन हमलों और साइबर अटैक जैसी नई चुनौतियों का उल्लेख इस नीति को आधुनिक बनाता है। सीमाओं पर ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थ गिराने की घटनाएं पिछले वर्षों में सामने आई हैं। साइबर हमलों के जरिए महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को निशाना बनाया जा सकता है। रासायनिक, जैविक या परमाणु हमलों की आशंका भले ही कम हो, लेकिन उनका

प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। इसलिए नीति में इन सभी संभावित खतरों के प्रति तैयारी और सतर्कता पर जोर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'प्रहार' केवल वर्तमान खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखती है। आतंकी संगठनों और संगठित अपराध गिरोहों के गठजोड़ पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कई बार आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन की व्यवस्था हवाला, मादक पदार्थों की तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों से की जाती है। यदि इन फंडिंग चैनलों को तोड़ा जाए और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को खत्म किया जाए तो आतंकवाद की जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। नीति में इस दिशा में कठोर कदम उठाने की बात कही गई है। इससे आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों पर चोट पहुंचेगी। भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में कानून-व्यवस्था मुख्यतः राज्य का विषय है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा में केंद्र की भूमिका प्रमुख होती है। यदि दोनों स्तरों पर समन्वय में कमी हो, तो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। 'प्रहार' में राज्यों की एटीएस और आतंकवाद रोधी इकाइयों की क्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और तकनीकी संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया गया है। इससे पूरे देश में एक समान और मजबूत आतंकवाद रोधी ढांचा तैयार किया जा सकेगा। नीति में मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने की बात भी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद से लड़ाई में कठोरता आवश्यक है, लेकिन कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया और अपील का अधिकार देना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। इससे सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम रहता है। यह संदेश भी जाता है कि भारत आतंकवाद से लड़ते हुए भी अपने संवैधानिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा।

कट्टरपंथ को रोकने के लिए युवाओं की समय रहते पहचान और परामर्श की व्यवस्था, जेलों में उग्र विचारधारा के प्रसार को रोकने के उपाय तथा शिक्षा और रोजगार के माध्यम से सामाजिक कमजोरियों को दूर करने की सोच नीति को केवल सुरक्षा दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी बनाती है। यदि युवा कट्टरपंथ की ओर आकर्षित ही न हों तो आतंकवादी संगठनों की भर्ती प्रक्रिया कमजोर पड़ जाएगी। इस दृष्टि से 'प्रहार' सामाजिक भागीदारी और पुनर्वास पर भी जोर देती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात इस नीति को वैश्विक आयाम देती है। अन्य देशों के साथ सूचना साझा करना, प्रत्यर्पण समझौते और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर आतंकियों को नामित कराने के प्रयास भारत की कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाते हैं। आतंकवाद आज सीमा-रहित चुनौती बन चुका है, इसलिए उसका समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही संभव है। 2004-14 की तुलना में 2014-25 के बीच घटनाओं और हताहतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति बताती है कि सुरक्षा तंत्र ने कुछ हद तक प्रभावी काम किया है। कुल मिलाकर, 'प्रहार' केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की समग्र सोच का प्रतिबिंब है। इसमें सुरक्षा, तकनीक, सामाजिक जागरूकता, कानूनी संतुलन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समावेश है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समन्वय स्थापित हुआ, और समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई तो निश्चित रूप से आतंकवाद की घटनाओं में और कमी लाई जा सकती है। यह नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को भटकाव से बचाने और राष्ट्र को स्थिर, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

दिवस विशेष
आचार्य दीप चन्द भारद्वाज

प्रखर राष्ट्रभक्त क्रांतिवीर थे विनायक दामोदर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि, वकील तथा प्रखर राष्ट्रभक्त नेता थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागपुर गांव में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। सावरकर बाल्यकाल से ही उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनका साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण हो गया था। दस वर्ष की आयु में ही उनकी कविताएं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगी थी। ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के उद्देश्य से सावरकर ने वर्ष 1899 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मित्र मेला नामक संगठन का गठन किया। बाद में संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सावरकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे।

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और कला स्नातक की डिग्री हासिल की इसके बाद वह कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर भी इस राष्ट्रभक्त

ने भारतीय छात्रों को स्वाधीनता हेतु प्रेरित किया और 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ना था। वर्ष 1909 में वीर सावरकर को मिंटो मार्ले रिफार्म के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में वारंट जारी किया गया। वर्ष 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 50 वर्ष की जेल की कठोर सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप सेल्यूलर जेल ले जाया गया। 27 वर्ष की आयु में सावरकर को दो बार काले पानी की सजा सुनाई गई थी। अंग्रेज सावरकर को दिनभर कोल्हू में बैल की जगह हांकते, तेल पिसवाते, रस्सी बंटवाते। इन समस्त यातनाओं को सहते हुए भी सावरकर जेल में कैदियों के भीतर राष्ट्र भक्ति की भावनाएं सुदृढ़ करते रहे। जेल की दीवारों पर इन्होंने कील और पत्थरों से 6000 राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत कविताएं लिख दी थी। भीषण अमानवीय यातनाओं के दौर को झेलते हुए वे जेल में बंद कैदियों को समझाते थे कि - 'धीरज रखो, एक दिन आएगा, जब यह जगह तीर्थ स्थल बन जाएगी। आज भले ही हमारा पूरे विश्व में मजाक बन रहा हो, एक समय ऐसा होगा, जब लोग कहेंगे कि देखो, इन्हीं काल कोठरियों में हिंदुस्तानी कैदी बंद थे। उन्हीं कैदियों की यहां प्रतिमाएं होंगी'। ये कलम और दिमाग दोनों से अंग्रेजों से लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। सावरकर पहले इतिहासकार थे, जिन्होंने 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। सावरकर ने ही यह साबित किया था कि यह सैनिक विद्रोह नहीं प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। उसने सभी अमर बलिदानियों की गाथा जन-जन तक पहुंचाई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी सावरकर द्वारा रचित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त की। दुनिया में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित किया गया हो। अंग्रेज सावरकर की इस पुस्तक से इतने भयभीत थे कि उन्होंने हर एक प्रयास किया, ताकि यह पुस्तक भारत तक न पहुंच सके। और जब सावरकर की यह पुस्तक क्रांतिकारियों में पहुंची तो क्रांति की ज्वाला में घी की आहुति पड़ गई। वर्ष 1924 में जेल से रिहा होने के बाद सावरकर समाज सुधार कार्य में लग गए। यह हिंदुत्व के प्रखर चिंतक थे। सावरकर जातिवाद के घोर विरोधी थे। रत्नागिरी में इन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की और छुआछूत मिटाने का कार्य किया। इनका संपूर्ण जीवन भारतीय स्वाधीनता एवं हिंदुत्व को समर्पित रहा। सावरकर ने 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया था। सावरकर को ओजस्वी वक्ता के रूप में भी जाना जाता है, अपने समर्थकों पर उनकी अमिट छाप थी। सावरकर ने दृढ़ता पूर्वक यह कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और जो एक रक्त में बंधे हैं।

इनका चिंतन था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के आदर्श प्रत्येक भारतवासी के लिए वंदनीय हैं। सावरकर ने अपनी युवावस्था भारतीय स्वाधीनता हेतु सेलुलर जेल की काल कोठरी में कठोर अमानवीय यातनाएं सहकर मृत्यु पर्यंत भारतीय हिंदू संस्कृति के उद्धार हेतु कार्य किया। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में इस महान देशभक्त ने अंतिम श्वास ली। निडर स्वतंत्रता सेनानी एवं हिंदुत्व के सूत्रधार सावरकर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि को समर्पित रहा।

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जन्म व मृत्यु के उपरांत समाप्त होती है यात्रा

संकलित
दर्शन

शरीर में समाहित ऊर्जापुंज को आत्मा कहा गया है। यह आत्मा अनंत ऊर्जा अर्थात परमात्मा का एक अति सूक्ष्म अंशमात्र है। भौतिक जगत में रहते हुए यह भौतिक शरीर एक यात्री के सदृश होता है। शरीर के जन्म के साथ ही यात्रा प्रारंभ होती है एवं मृत्यु के उपरांत समाप्त हो जाती है। अर्थात भौतिक शरीर के लिए जीवन एक यात्रा के समतुल्य है। जन्म के साथ ही ऊर्जापुंज अर्थात आत्मा भौतिक शरीर से संयुक्त होकर उसकी यात्रा में सहयात्री की भूमिका का निर्वहन करने लगता है एवं मरणोपरांत स्वयं को यात्रा से अलग कर लेता है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक शरीर की यात्रा का आदि और अंत स्पष्टतः ज्ञात होता है, परंतु ऊर्जापुंज जिसे आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, अपनी यात्रा के आदि और अंत से सर्वथा अपरिचित होता है। आत्मा की यात्रा कब और क्यों प्रारंभ हुई तथा कब और क्यों पूर्ण होगी? इन प्रश्नों का हल आज भी एक चुनौती के रूप में खड़ा है। ऊर्जापुंज अगणित भौतिक शरीरों की भौतिक यात्रा में सहयात्री की भूमिका को निभाता हुआ अपनी अनंत दिव्ययात्र को जारी रखता है। अर्थात आत्मा की इस अलौकिक यात्रा में अनंत लौकिक यात्राएं शामिल होती हैं। इस अलौकिक यात्रा के संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह यात्रा अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही पूर्ण होगी, किंतु अनंत को परिभाषित करना भी असंभव है। अनंत को अज्ञात का पर्याय माना जा सकता है।

जीवन में ईश्वर की दया ही है सब

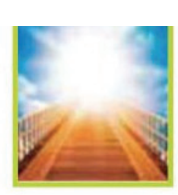

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था, संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछाः ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गये? नौकर बोलाः आप मेरे मालिक है, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते है, अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया, अगर ईश्वर ने इतनी सुख-सम्पदाएँ दी है, और कभी कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं।

असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है, सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम केवल जीवन में अच्छे व उजले पक्ष को ही देखते हैं। हमें सुख, आराम पसंद है, पर दुख व कष्ट के क्षण आते ही हमारा मन विचलित होने लगता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही पल होते हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द: एक इस्लामी दायित्व और भारत में संवैधानिक कर्तव्य

सैय्यद जाहिद अली रियासत

भारत की विविधता कोई संयोग नहीं, बल्कि संवैधानिक संकल्प है। भाषाएँ, धर्म, जातियाँ, संस्कृतियाँ और जीवन-शैलियाँ इसलिए साथ-साथ मौजूद हैं क्योंकि इस गणराज्य ने उन्हें संरक्षण देने का निर्णय लिया है। करोड़ों भारतीय मुसलमानों के लिए यह संवैधानिक वादा उनके धार्मिक विवेक से गहराई से जुड़ता है। इस्लाम बहुलतावादी समाजों से उदासीन नहीं है; बल्कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, न्याय और विविधता की रक्षा को नैतिक दायित्व मानता है। जब इस्लामी शिक्षाओं और भारतीय संविधान को साथ पढ़ा जाता है, तो वे एक-दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि परस्पर सहयोगी दिखाई देते हैं। इसलिए भारत में सांप्रदायिक सौहार्द केवल नागरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए यह ईमान का हिस्सा और संविधान के प्रति निष्ठा दोनों है। भारतीय संविधान ह्लहम, भारत के लोगह्व शब्दों से आरंभ होता है – यह एक सामूहिक पहचान है जो धर्म, जाति और भाषा से ऊपर है। यह कुरआन के उस मूल सिद्धांत की प्रतिध्वनि करता हैः ह्लनिश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मानित किया।ह्व (कुरआन 17:70) इस्लाम प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा को स्वीकार करता है, केवल मुसलमानों की नहीं। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और जन्म या विश्वास के आधार पर किसी भी भेदभाव को अस्वीकार करता है। दोनों ही ढाँचे इस विचार को नकारते हैं कि सम्मान और अधिकार चुनिंदा लोगों तक सीमित किए जा सकते हैं। जब सांप्रदायिक हिंसा किसी व्यक्ति की सुरक्षा और मानवता को छीन लेती है, तो वह संवैधानिक नैतिकता और इस्लामी आचार दोनों का उल्लंघन करती है। कुरआन की चेतावनी हैः ह्लजिसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, उसने मानो समस्त मानवता की हत्या की।ह्व (कुरआन 5:32) इसका संवैधानिक समकक्ष अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन की रक्षा किसी शर्त पर निर्भर नहीं, बल्कि पूर्ण और अनिवार्य है। भारत केवल विविधता को सहन नहीं करता, बल्कि उसे संरक्षित करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता मिलती है। इस्लाम विविधता को ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानता हैः ह्लहमने तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में इसलिए बनाया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो।ह्व (कुरआन 49:13) भिन्नता का उद्देश्य प्रभुत्व नहीं, बल्कि पारस्परिक परिचय और सम्मान है। यह भारत की बहुलतावादी भावना से मेल खाता है, जहाँ एकता समानता थोपने से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान से बनती है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सबसे बड़ा खतरा वह सोच है जो अपने समूह के प्रति निष्ठा के नाम पर दूसरों के साथ अन्याय को उचित ठहराती है। इस्लाम और संविधान दोनों इसे सख्ती से अस्वीकार करते हैं। कुरआन कहता हैः ह्लन्याय पर दृढ़ रहो, चाहे वह तुम्हारे अपने विरुद्ध ही क्यों न हो।ह्व (कुरआन 4:135) यह संविधान के ह्यकानून के शासनह्ण के सिद्धांत से मेल खाता है, जहाँ न्याय किसी पहचान के आधार पर नहीं बदलता। पैगंबर मुहम्मद ने ह्यअसबीयाह्ण (अंधा सामुदायिक पक्षपात) के विरुद्ध चेतावनी दी और उसे इस्लामी भावना के विपरीत बताया। भारत जैसे बहुधर्मी समाज में यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। जब पैगंबर मुहम्मद ने मदीना में एक नगर-राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने ह्यमदीना का संविधानह्ण नामक एक सामाजिक समझौता लागू किया, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और अन्य कबीलों को समान अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक राजनीतिक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। यह प्रारंभिक संवैधानिक प्रयोग भारतीय संवैधानिक मूल्यों से सामंजस्य रखता है। भारतीय संविधान भी विभिन्न धार्मिक समुदायों को मान्यता देता है, आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अन्याय के विरुद्ध सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। इसलिए गैर-धर्मतांत्रिक संविधान के अंतर्गत निष्ठापूर्वक जीवन जीना आस्था से समझौता नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का समर्थन है। सांप्रदायिक सौहार्द केवल कानूनी प्रावधानों से जीवित नहीं रहता; वह दैनिक नैतिक व्यवहार से सुदृढ़ होता है। इस्लाम पड़ोसियों के प्रति दया और सुरक्षा पर विशेष बल देता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। पैगंबर ने कहाः ह्लवह सच्चा ईमान वाला नहीं, जिससे उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।ह्व (सहीह बुखारी) संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित ह्यबंधुताह्ण (ऋ१३१ल्ल३८) का मूल्य इसी करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस्लाम घृणा-भाषण और सामूहिक अपमान की कठोर निंदा करता है। कुरआन निर्देश देता हैः ह्लतुम उनके पूज्य वस्तुओं को अपमानित न करो, जिन्हें वे ईश्वर के अतिरिक्त पूजते हैं, अन्यथा वे अज्ञानवश शत्रुता में ईश्वर का अपमान करेंगे।ह्व (कुरआन 6:108) यह सिद्धांत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उन उचित प्रतिबंधों से मेल खाता है, जो सांप्रदायिक घृणा को रोकने के लिए हैं। जिम्मेदार अभिव्यक्ति दमन नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन है। पैगंबर के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि अपने वतन की रक्षा, संधियों का सम्मान और जनकल्याण को प्राथमिकता देना धार्मिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारतीय मुसलमानों के लिए संविधान का सम्मान करना, धर्मनिरपेक्ष कानून का पालन करना और सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य करना तुष्टीकरण नहीं, बल्कि इबादत का एक रूप है। संविधान के प्रति निष्ठा आस्था को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे सशक्त बनाती है। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द केवल एक समुदाय का दायित्व नहीं है। फिर भी मुसलमानों के लिए यह विशेष नैतिक महत्व रखता है। इस्लाम विश्वासियों से अपेक्षा करता है कि वे विविध समाजों में जीवन, गरिमा और शांति के रक्षक बनें। भारतीय संविधान कानूनी ढाँचा प्रदान करता है और इस्लाम नैतिक दिशा देता है। दोनों मिलकर एक ऐसे समाज का आह्वान करते हैं जहाँ भिन्नताएँ विभाजन में न बदलें और आस्था भय का कारण न बने।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

ट्रेंड

भारत माता का अपमान

मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कृषि समझौते भारत के किसानों के हित में हैं। कुछ लोग गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई कॉन्फ्रेंस में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारे। ये भारत माता का अपमान है।
-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

कांग्रेस की कार्यशैली

सत्ता की लालसा में राष्ट्रहित से समझौता करना कांग्रेस की पीढ़ीगत कार्यशैली रही है। आज भी इनके नेता देश और विदेशी धरती पर जाकर भारत की साख को धूमिल करने तथा दुश्मन देशों से मदद की गुहार लगाने में संकोच नहीं करते।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

सच्चाई जनता को बताएं

निवेश के नए आंकड़े देने से पहले पुराने समझौतों की सच्चाई जनता को बताइए। यूपी की भाजपा सरकार ने दिखाए तो करोड़ों के एमओयू लेकिन जमीन पर इनके बनाये हवाई अड्डों की तरह कुछ भी नहीं उतरा।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

तकनीकी इस्तेमाल

अगर चीन रोबोट का इस्तेमाल कचरा इकट्ठा करने, सीवर साफ करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? आइए, तकनीकी विशेषज्ञों, इस चुनौती को स्वीकार करें - कचरे को धन में बदलें और एक स्वच्छ और हरा-भरा शहर बनाएं।
- किरण मजूमदार, उद्यमी

ग्रेड आधारित लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए

एजेंसी

नयी दिल्ली। सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जिम्मेदारी से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए ग्रेड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंक काटे जाएंगे और गंभीर या बार-बार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 1.8 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में जाने या नशे में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है। राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार सड़क सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। गडकरी ने बताया कि सरकार पहले ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने कहा हम ड्राइविंग लाइसेंस में ग्रेडेड अंक प्रणाली ला रहे हैं। मंत्री ने समझाते हुए कहा कि यातायात उल्लंघन पर कुछ अंक काटे जाएंगे। यदि सभी अंक समाप्त हो जाते हैं तो दोषी का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है या अपराध दोहराने पर रद्द भी किया जा सकता है। यह योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.8 लाख लोगों की जान जाती है।

उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से 72 प्रतिशत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 10,119 लोगों की दुर्घटनाओं में जान गई। हेलमेट का उपयोग न करने से 54,122, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने से 14,466 जबकि तेज रफ्तार के कारण 1.2 लाख लोगों की जान गई। अन्य प्रमुख कारणों में गलत दिशा में व नशे में वाहन चलाना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल शामिल हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें और उपचार खर्च या कानूनी औपचारिकताओं की चिंता न करें। पीएम राहत योजना (रोड एक्सिडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट) के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन सहायता प्रणाली उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से सात दिन तक 1.5-1.5 लाख रुपये तक का नकद रहित (कैशलेस) उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

बिरला ने न्यायाधीश वर्मा को हटाने के कारणों पर जांच करने वाली समिति का किया पुनर्गठन

एजेंसी

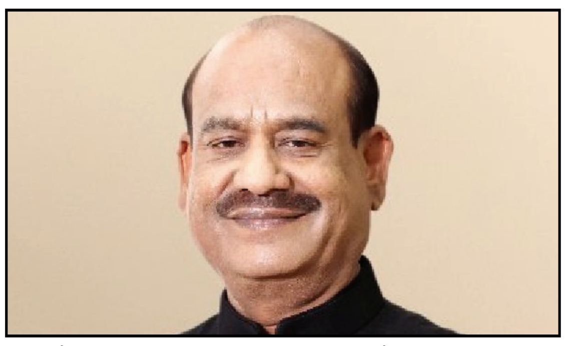

नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले साल मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में उन्हें पद से हटाने के कारणों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है। लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि समिति को 26 फरवरी से तीन महीने का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। बिरला ने पिछले साल 12 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए एक बहुदलीय नोटिस स्वीकार करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया को तेज करते हुए समिति का गठन किया था। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए जिन कारणों पर विचार की प्रार्थना की गई है, उनकी जांच के लिए तीन सदस्यों वाली समिति का आंशिक संशोधन के साथ पुनर्गठन किया है। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति कुमार और आचार्य पिछली समिति का भी हिस्सा थे, न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर नए सदस्य हैं। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 5 मार्च को 62 वर्ष का हो जाने पर पदमुक्त हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जांच समिति ने कार्य पूरा करने में एक और वकील की सहायता मांगी है। समिति की कार्यवाही अदालतों के कामकाज के तरीके से आयोजित की जाती है, जहां आरोपी अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नकदी की बरामदगी के बाद, न्यायमूर्ति वर्मा को वापस उच्च न्यायालय, इलाहाबाद भेज दिया गया था।

संक्षेप

बिजली ग्रिड 50 वर्षों के लिए हो रहे तैयार

नयी दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को चांदनी चौक में बिजली के तारों को जमीन के नीचे करने की परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार अगले 50 साल के लिए शहर की बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। गुप्ता ने बताया कि कूचा महाजनी, भागीरथ पैलेस, जामा मस्जिद रोड और नयी सड़क समेत पुरानी दिल्ली के 28 इलाके बिजली के लटकते तारों से मुक्त हो जाएंगे। इस परियोजना की लागत 160 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, जिसका सीधा असर बिजली की मांग पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन को स्मारक के रूप में पुनर्जीवित करेगी।

विहिप करेगा राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन

एजेंसी

जोहानिसबर्ग। विश्व हिंदू परिषद की दक्षिण अफ्रीका शाखा की ओर से शनिवार को प्रिटोरिया में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का विषय द नेशनल रीसेट ए विजन फॉर ए प्रोग्रेसिव साउथ अफ्रीका रखा गया है। इसमें देशभर से आध्यात्मिक नेता, शिक्षाविद, पेशेवर, युवा प्रतिनिधि और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता के बाद हो रहा है, जिसमें दर्जनों हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर अधिक समन्वय, वकालत और प्रतिनिधित्व की साझा मांग उठाई थी। आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष का कार्यक्रम केवल संवाद तक सीमित न रहकर ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर केंद्रित होगा, जिसमें सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय योगदान के लिए व्यावहारिक कदमों की रूपरेखा बनाई जाएगी।

ब्रिटेन में हिंदू मंदिर के बंद होने का खतरा

एजेंसी

लंदन। पूर्वी ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में एक परिसर में मौजूद 40 साल पुराने हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर के बंद होने का डर है, क्योंकि स्थानीय

काउंसिल ने भवन को बेचने का निर्णय लिया

प्राधिकारियों ने इस भवन को बेचने के फैसले को सही ठहराया है जो मंदिर के लिए किराये पर दिया गया है। भारत हिंदू समाज मंदिर की स्थापना 1986 में शहर के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में हुई थी और कैम्ब्रिजशायर, नॉरफॉक तथा लिंकनशायर के बड़े इलाके के 13,000 से अधिक हिंदू यहां दर्शन करने आते हैं।

मंदिर प्रशासन पीटरबरो सिटी काउंसिल से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए अभियान चला रहा है। इस महीने की शुरुआत में काउंसिल कैबिनेट की बैठक में यह कहा गया कि संपत्ति की बिक्री से करदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य दिलाने की उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। वहीं, मंदिर ने एक बयान में कहा, हम भारत हिंदू समाज से जुड़े भवन की बिक्री की कड़ी निंदा करते हैं।

समुदाय द्वारा बनाई गई संस्था को बंद दरवाजों के पीछे बिना पारदर्शिता या सहमति के नहीं बेचा जाना चाहिए। इसमें कहा गया, यह सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि विरासत, भरोसे और जवाबदेही के बारे में है। समुदाय जवाब पाने का हक रखता है, गोपनीयता का नहीं। इस फैसले पर सवाल उठाए जाने चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

अनिल अंबानी और आर फॉम के खिलाफ 2,220 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी एवं रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने और बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मंगलवार को बैंक से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालयों पर छापेमारी की है। इस ज ण लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा, प्राथमिकी में आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिये गए ज णों के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

भारत, उत्तर कोरिया नही सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो लोकतंत्र मर जाता है : राहुल

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर असहमति को अपराध बना देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह समझना चाहिए कि भारत उत्तर कोरिया नहीं है और जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे तो लोकतंत्र मर जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है तथा सवाल पूछने से लोकतंत्र मजबूत होता है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज भारत में कंप्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना

दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साज़िश बताया जाता है। उन्होंने कहा, सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमा और जेल, यह लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब लाठियों से मिला। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने भाजपा के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया, और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ तो न्याय की मांग (रहे प्रदर्शनकारियों) को व्यवस्था के लिए असुविधौ मानकर हटा दिया गया। उन्होंने कहा, युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले व्यापार समझौते का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देशविरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया।

न्यायिक भ्रष्टाचार के एनसीईआरटी अध्याय पर प्रतिबंध

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की उन किताबों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने के इरादे से की गई सुनियोजित साजिश है, साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार पर अध्याय से संबंधित कक्षा आठ की सभी किताबों, उनकी प्रतियों और डिजिटल स्वरूपों को जब्त करने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, उन्होंने ऐसा आघात किया है, जिससे न्यायपालिका आहत हुई है। एक दिन पहले प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीईआरटी को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अनुचित सामग्री के लिए माफी मांगने और उचित अधिकारियों से परामर्श करके इसे फिर से लिखने की बात कही थी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। पीठ ने एनसीईआरटी के निदेशक और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी

उच्चतम न्यायालय

चाहिए। एनसीईआरटी के बुधवार के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह (पत्र) अपने आप में गहरी साजिश को दर्शाता है। एक सुनियोजित साजिश। पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की सोची-समझी साजिश रची जा रही है। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर उसके निर्देशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया तो गंभीर कार्वाई की जाएगी। पुस्तक की सामग्री का हवाला देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के व्यवहार का न्यायपालिका पर गहरा असर पड़ेगा।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव जिला जशपुर के न्यायालय मे मामला क्रमांक: 202602031100037

विषय:- अ-2
मामले की श्रेणी:- राजस्व
सत्त:- 2025-2026
पत्थलगांव प.ह.न. 00006 [65/1/ख/8(0.0080 हे0)]
पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार पुरुषोत्तम बल्द लक्ष्मी चंद,
अनावेदक पक्षकार -छ.ग. शासन,

ईश्तहार

एतद द्वारा समस्त आम जनता ग्राम पत्थलगांव प.ह.न. 06, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुरुषोत्तम बल्द लक्ष्मी चंद जाति अग्रवाल निवासी ग्राम पत्थलगांव तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) के द्वारा सारिणी में उल्लेखित ग्राम पत्थलगांव प. ह. नं. 06 स्थित आवेदित भूमि ख.नं. 65/1/ख/8 शामिल नं0 68/27/8 रकबा 0.008 हे0 (81.04 वर्गमीटर) का आवासीय प्रयोजनार्थ (मकान निर्माण) के लिये व्यपवर्तन कराये जाने हेतु, मय आवेदित भूमि के नक्शा, खसरा, बी-1 एवं रजिस्ट्री की छायाप्रति सहित छ.ग.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 18/03/2026 को स्थान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के न्यायालय में न्यायालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक होना नियत किया गया है, अतः इसमें जिस किसी भी व्यक्ति को दाबा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत दिनांक/समय / स्थान को मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/02/2026 को जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,
पत्थलगांव जिला जशपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/अ-20(1)/2025-26,
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अभिषेक दुबे आ० स्व० रविन्द्र नाथ दुबे व अन्य 24 सभी जाति ब्राह्मण, मूल निवासी मोहल्ला प्रतापपुर नाका के पास, शिवधारी कॉलोनी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला बाबूपास, नगर अम्बिकापुर, शीट नंबर 09 स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3323/6, 3323/7 रकबा कमशः 0.73, 0.05 एकड़ की लीज समाप्ति तिथि 31.03.2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र मय मॅटनेश खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 17/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-03 जिला-सरगुजा (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०-202602022900005/ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शशि कश्यप पति अजय कुमार कश्यप, निवासी कृष्णा गली मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा कमांक 338/8 रकबा 0.020 हे० भूमि को अनावेदिका प्रतिमा सोनी पति धर्मेन्द्र सोनी निवासी महामाया मंदिर के पास. अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के पास बिकी करने की अनुमत्ति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान्‌कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 12/03/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अमिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 23/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-03

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/अ-20(1)/2025-26,
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक फैजुल हसन फिरदौसी पिता स्व० डॉ० नुरुल हसन फिरदौसी, निवासी मनेन्द्रगढ़ रावत रेसीडेन्सी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला देवीगंज रोड़, नगर अम्बिकापुर, शीट नंबर-03 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 989/3 रकबा 0.012 एकड़ भूमि की लीज समाप्ति तिथि 31/03/2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मय मेंटनेश खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांक- 19/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

मिशन बेटियां गेटेम्बे फाउंडेशन ने घोषित की नई जिला कार्यकारिणी

उर्वशी साहू बनीं जिला संयोजक, शैलेन्द्र जैन सहसंयोजक और विजय पाल सिंह सचिव नियुक्त

गोरखपुर। बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर कार्य कर रही सामाजिक संस्था मिशन बेटियां गेटेम्बे फाउंडेशन ने अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत जनपद स्तर पर नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। संस्था की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उर्वशी साहू को जिला संयोजक, शिक्षक एवं ए.आर.पी. शैलेन्द्र जैन को सहसंयोजक तथा शिक्षक सरदार विजय पाल सिंह (सन्नी) को जिला सचिव नियुक्त किया गया है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि मिशन बेटियां गेटेम्बे फाउंडेशन पिछले एक दशक से अधिक समय से बेटियों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्था द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान, शैक्षिक मार्गदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक संवाद और महिला सशक्तिकरण से जुड़े आयोजन किए जाते रहे हैं। नव-नियुक्त जिला संयोजक उर्वशी साहू ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जल्द ही जनपद के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकताओं, चिकित्सकों और युवाओं को जोड़कर एक सक्रिय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिससे संस्था के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। सहसंयोजक शैलेन्द्र जैन ने बताया कि संस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक सोशल मीडिया टीम गठित की जाएगी, जो संस्था की गतिविधियों और योजनाओं को व्यापक स्तर पर प्रचारित करेगी। उन्होंने पारदर्शिता, संवाद और सहभागिता को संगठन की प्राथमिकता बताया। वहीं, नवनियुक्त जिला सचिव विजय पाल सिंह (सन्नी) ने कहा कि संस्था का मूल उद्देश्य परोपकार और समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समाज और राष्ट्र की सेवा करना होना चाहिए। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही एक व्यापक सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और युवाओं को जोड़कर एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नई जिला टीम के गठन के साथ संस्था ने विश्वास जताया है कि मिशन बेटियां गेटेम्बे फाउंडेशन बेटियों के सर्वांगीण विकास, नारी सम्मान और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा। संगठन ने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया

किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से आज उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। इससे पहले किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि धान के अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले से इस राशि का अंतरण किया जाएगा और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी किसानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर सहित प्रदेश भर से आए किसान उपस्थित थे।

व्यावहारिक कौशल से समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में चिकित्सक निभाएंगे अग्रणी भूमिका - स्वास्थ्य मंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर द्वारा आयोजित पी. जी. डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के दीक्षांत समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समारोह में सफलतापूर्वक डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले सभी डॉक्टरों को प्रमाणपत्र प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह पाठ्यक्रम चिकित्सा पेशेवरों की उत्कृष्ट शिक्षा, समर्पण एवं सेवा भावना को मान्यता प्रदान करता है। फैमिली मेडिसिन की यह विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था न केवल चिकित्सकों के कौशल को सुदृढ़ करती है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संदेश में कहा कि संस्थान से प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के माध्यम से ये सभी चिकित्सक समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे तथा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में योगदान देंगे। समारोह के दौरान डिप्लोमा प्राप्त करने वाले सभी डॉक्टरों को उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

मुख्यमंत्री ने दी जशपुर जिले को बड़ी सौगात, 30.59 करोड़ की 9 सड़कों को मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को विकास की नई रफ्तार देते हुए 9 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए कुल 30 करोड़ 59 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होगा, व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। दो वर्षों के भीतर मिली इस करोड़ों की सौगात से जिले की सड़क व्यवस्था का व्यापक कायाकल्प हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक पहल बताया है। जिले के ढूंड़गजोर (सरसमार) से चिढ़रापारा पत्थलगांव तक 2 किमी 1 करोड़ 96 लाख, ग्राम ढोंगादरहा से अम्बाकछार मार्ग 3 किमी 4 करोड़ 84 लाख, ग्राम पंचायत मुड़ापारा (हड्डी गोदाम मेन रोड) से घिंचापानी होते हुए पंगसुवा मार्ग 4.85 किमी 4 करोड़ 26 लाख, ग्राम कोतबा से सरईकोना होते हुए पिकपारा मार्ग 4.60 किमी 4 करोड़ 59 लाख, कांसाबेल के बटाईकला प्रेमनगर से मारचाईढोढ़ी मार्ग 2.90 किमी, 2 करोड़ 79 लाख, कांसाबेल खूंटीटोली बस्ती से चेतबा हाई स्कूल मार्ग 2 किमी 2 करोड़ 4 लाख, कांसाबेल कोरंगा से नवाटोली से भागलपुर मार्ग 2 किमी 2 करोड़ 14 लाख, कुड़केल खजरी के पटेल पारा से बगई झरिया मार्ग 3.80 किमी 3 करोड़ 28 लाख, कोकिया खार से आमकानी मेन रोड तक 4 किमी 4 करोड़ 69 लाख रुपए की मंजूरी मिली है।

सीएम हेल्पलाईन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली से जनसामान्य की शिकायतों का होगा निराकरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग की सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लोगों द्वारा विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी। इसमें दूरभाष, व्हाट्सएप, पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी। मुख्यमंत्री के जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों के आवेदनों निराकरण भी सीएम हेल्पलाईन से किया जा सकेगा एवं जिलों में कलेक्टर द्वारा जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों को भी सीएम हेल्पलाईन में दर्ज किया जाएगा। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहूल भगत की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाईन योजना हेतु नामांकित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों एवं सहायक नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण सह बैठक का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में तकनीकी सपोर्ट टीम द्वारा अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन के तहत कार्य करने का प्रेजेंटेशन के जरिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहूल भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसामान्य की शिकायतों का निराकरण शीघ्रता से हो, इसके लिए सीएम हेल्पलाईन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से शिकायतों को पंजीकृत कर निर्धारित समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण होगा। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वे प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करें। राज्य शासन के विभागों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत किया जाएगा।

शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर पूरे समाज का विकास होना चाहिए- रमेन डेका

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर पूरे समाज का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और शिक्षा हमारे जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। अगर हम अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में पीछे छूट रहे लोगों का जीवन सुधार पायें उनकी जिंदगी बेहतर बना पायें तो हमारा जीवन सफल होगा और इस अनमोल मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। दीक्षांत समारोह में 816 स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट विद्यार्थियों को उपाधियाँ और पदक प्रदान किए गए। शेल इंडिया की अध्यक्ष और शेल लुब्रिकेंट्स एशिया पैसिफिक की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंसी मदन त्रिपाठी को विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (ऑनोरिस काउसा) से सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका आज एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए ज्ञान का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी अंतर आत्मा से साक्षात्कार करते रहना चाहिए ताकि हम सही और गलत में अंतर समझ सकें। अंतरात्मा की सुनेंगे वो आपको कभी गलत काम करने नहीं देगी और इसी तरह आप खुद को ईश्वर के नजदीक पायेंगे और आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। शिक्षा से हम ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और हमें शिक्षा में भी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें हमें तकनीक का उपयोग करके जीवनशैली को बेहतर बनाना सिखाती है। लेकिन हमें अपने समाज, राष्ट्र और संस्थान के लिए भी अपना योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा अब आप किसी भी उम्र में अपने पसंद की डिग्री हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि करियर निर्माण की आपा धापी में हम अपना पैशन भूल जाते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं है, खुशी और आत्म संतुष्टि प्राप्त करना भी है इसलिए हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। इस अवसर पर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आठ छात्रों को बलजीत शास्त्री पुरस्कार, 31 छात्रों को डॉ. अशोक के. चौहान पुरस्कार, और 20 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने किया गुलाल होली विशेषांक का विमोचन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में गुलाल होली विशेषांक का विमोचन किया। वरिष्ठ पत्रकार जगजीत सिंह द्वारा प्रकाशित इस विशेषांक में होली पर्व के सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक पक्षों को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे और भारतीय परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति का पर्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकाशन हमारी लोकसंस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस रचनात्मक पहल के लिए प्रकाशक और उनकी टीम को बधाई दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, दीपक विश्वकर्मा, नदीम मेमन तथा श्रमजीवी गिल्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष आर.के. गांधी उपस्थित थे।

स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है सिटी गैस परियोजना : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएनजी युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रायपुर नगर निगम की पहली पाइपलाइन गैस उपभोक्ता श्रीमती पूनम चौबे से संवाद कर घरेलू उपयोग में पाइपलाइन गैस की सुविधा के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इन वर्षों में प्रदेश ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। सिटी गैस अवसंरचना परियोजना इस विकास यात्रा में एक नई उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल नई सुविधा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अधोसंरचना की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मेट्रो शहरों की तर्ज पर डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को रिफिलिंग की झंझट से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सस्ती और सुलभ ऊर्जा मिलने से उद्योग क्षेत्र को भी गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने एचसीजी समूह को बधाई देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे रायपुर सहित बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में शीघ्र ही सीएनजी स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों के ईंधन खर्च में भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत राज्य बजट में अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे पुनर्वासित युवा: विधानसभा में समझी जनतांत्रिक प्रणाली

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। माओवाद की विचारधारा त्यागकर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित युवाओं के दल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। युवाओं ने सदन की कार्यवाही को करीब से देखा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा। विधानसभा का यह शैक्षणिक भ्रमण उनके लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक अनुभव साबित हुआ। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सभी का ह्यजय जोहार के साथ स्वागत करते हुए कहा कि पुनर्वास का निर्णय लेने वाले सभी साथियों का राज्य सरकार हृदय से अभिनंदन करती है। उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वासित युवाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी पुनर्वासित युवा समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से पुनर्वास नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग छोड़कर आज संविधान के मंदिर में खड़े होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साक्षी बनना इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा ह्यगनतंत्र का रास्ता छोड़कर गणतंत्र की मुख्यधारा में लौटे हैं, उनका राज्य सरकार हृदय से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि संविधान का मार्ग ही शांति, विकास और समृद्धि का मार्ग है। राज्य सरकार पुनर्वासित युवाओं के सम्मानजनक जीवन, रोजगार और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनेंगे और अन्य लोगों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक किरण देव तथा सुशांत शुक्ला ने भी पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि शासन उनके साथ दृढ़ता से खड़ा है। पुनर्वासित युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को निकट से देखने का यह अवसर उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायी रहा। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे अब संविधान और कानून के दायरे में रहकर समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि 120 सदस्यीय इस दल में 66 पुरुष एवं 54 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। पुनर्वासित युवाओं का यह समूह तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत रायपुर पहुंचा है, जहां वे शासन-प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं, कार्यप्रणालियों एवं विकासात्मक पहलों से अवगत हो रहे हैं।

होली पर सड़क में नहीं चलेगी हुड़दंगी, तोड़े नियम तो होगी सख्त कार्रवाई : प्रशांत

0 एसएसपी ने अपराध समीक्षा बैठक में दिए निर्देश 0 लंबित मामलों के निराकरण की धीमी गति पर प्रभारियों को लगाई जमकर फटकार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। होली पर सड़क में हुड़दंग मचाने एवं नियम तोड़ने वालो पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। त्यौहार के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिले की पुलिस ने सख्त रूख अपनाया है। शुक्रवार को यहां जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना-चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए है। जिसमे उन्होंने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कर्तव्य निर्वहन, लंबित मामलों, शिकायतों व ऑनलाईन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में विलंब करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।अपराध सभा में एसएसपी ने लंबित अपराधों, शिकायतों, गुम इंसान के मामलों की समीक्षा कर जल्द और विधिसंगत निराकरण के निर्देश दिए। धारा 173(8) के लंबित मामलों के निराकरण की धीमी गति पर प्रभारियों को

कड़ी फटकार लगाई और उन्हें आरोपियों की गंभीरतापूर्वक पतासाजी कर जल्द गिरफ्तारी सहित विधि संगत निराकरण करने के निर्देश दिए।

होलिका दहन की रात और होली के दिन पुलिस की रहेगी कड़क सुरक्षा

एसएसपी श्री ठाकुर ने निर्देश दिए कि होलिका दहन की रात्रि एवं होली के दिन शहर के प्रमुख मार्गो, भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों तथा चौक-चौराहों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा प्रबंध कर ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से सघन वाहन चेकिंग की जाए, एसएसपी ने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाने, स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइसेंसर, तेज सख्त कार्रवाही की जाए। होली पर्व के पूर्व थाना-चौकी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों की होली शांती समिति की बैठक ली जाए।बैठक में प्रभारियों को निर्देशित किया कि थाने आने वाले फरियादियों की शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई करें, अधिनस्थ अधिकारी व जवानों से वन टू वन चर्चा कर उनके कार्य की अपडेट ले और उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। समंस-वारंटों को तामीली में कोताही ना बरते, निगरानी व गुण्डा बदमाशों की विधिवत् चेकिंग करने, एनडीपीएस एक्ट के मामले में इंड टू इंड विवेचना करने, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं सभी विवेचक-जवानों को कम्प्यूटर तकनीकी कार्यो में दक्ष बनाने की दिशा में कार्य करने कहा और इस दिशा में थाना प्रतापपुर व चंदौरा द्वारा बेहतर कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त किया। एसएसपी श्री ठाकुर ने नागरिकों से अपील किया है कि होली पर्व को मर्यादित और सुरक्षित वातावरण में मनाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाए, यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं तथा अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अपराध संबंधी सूचना हेतु सूरजपुर पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 94791-93999 पर संपर्क करें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, सीएसपी बेनार्ड कुजूर, डीएसपी अनूप एक्का, रीता नीलम कुजूर, डीएसपी अजाक पी.डी.कुजूर, जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

दो माह से नहीं मिला वेतन, आर्थिक तंगी से जूझ रहे एनएचएम कर्मचारी

होली से पहले वेतन जारी करने की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एनएचएम कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हैं। एनएचएम संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने बताया कि होली जैसे बड़े त्यौहार के नजदीक होने के बावजूद कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी के बजाय चिंता साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में बिना वेतन परिवार का भरण-पोषण, वृद्ध माता पिता की दवाई घर का किराया, इस परीक्षा के बच्चों का स्कूल का फीस, अत्यंत कठिन हो गया है। कर्मचारियों के सामने अपने बच्चों एवं परिवार के लिए त्यौहार की आवश्यक वस्तुएँ खरीद पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। यदि समय पर वेतन जारी नहीं हुआ तो इस बार भी होली फीकी रहने की आशंका है। प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि में वर्षभर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को ही त्यौहार के समय वेतन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। उन्होंने शासन एवं विभागीय अधिकारियों से कर्मचारियों की पीड़ा को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव एवं उच्च अधिकारीयों द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासनों के बावजूद वेतन जारी करने में देरी क्यों हो रही है। साथ ही एनएचएच कर्मचारियों की 6 जायज मांगों को लंबित रखना उचित नहीं है।

संघ ने स्पष्ट किया कि एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि मजबूरी में कर्मचारी आंदोलन या हड़ताल का रास्ता अपनाने को बाध्य होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। संघ के जिलाध्यक्ष डॉ बृज लाल पटेल ने शासन-प्रशासन से मांग है कि कर्मचारियों का लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक होली का त्यौहार मना सकें।

सोनपुर के प्रस्तावित चेक डैम स्थल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को कलेक्टर एस जयवर्धन द्वारा रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम सोनपुर में डीएमएफ मद से प्रस्तावित चेक डैम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसान, क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्माण की आवश्यकता, संभावित लाभ एवं तकनीकी पहलुओं के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की उपस्थिति, आयुष्मान कार्ड निर्माण की अद्यतन स्थिति, आधार सुधार कार्य की स्थिति, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों की उपलब्धता इत्यादि विषयों पर चर्चा कीं। इसके साथ ही उन्होने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के संबंध में ग्रामवासियों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी क्षेत्र की आवश्यकताओं और समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर, जनपद सीईओ संजय राय सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री करेंगे कृषक उन्नति योजना की राशि का अंतरण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान बेचने वाले जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले के 45 हजार 937 किसानों के बैंक खातों में कुल 221 करोड़ 14 लाख 40 हजार रुपये की अंतर राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

इस कार्यक्रम के तहत 28 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम रहंगी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दोपहर 12 बजे प्रदेश भर के किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। जिले में भी कृषक उन्नति योजना के तहत सभी विकासखण्डों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।

निरक्षर महिलाओं को साक्षरता से जोड़ने, 2 मार्च तक होगा सघन सर्वे

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वसहायता समूहों की निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षरता से जोड़ने के लिए कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2 मार्च तक ग्राम स्तर पर सघन सर्वे कराते हुए स्वसहायता समूहों की समस्त निरक्षर महिलाओं की पहचान किए जाने के लिए जिले के जिला परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में सभी विकासखंड के परियोजना प्रबंधकों को जिमेदारी दी गई है। समस्त जानकारी विकासखंड परियोजना अधिकारी लेट्रेसी को उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे के पश्चात चिह्नित निरक्षर महिलाओं को उनके ही ग्राम ,पारा,टोला ,मोहल्ला के उल्लास साक्षरता केंद्रों पर कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है इन महिलाओं को भी पठन पाठन में शामिल किया जाएगा । कक्षाओं की गुणवत्ता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु जिला, विकासखंड, संकुल एवं ग्राम स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इन महिलाओं को 22 मार्च को आयोजित होने वाले महापरीक्षा अभियान से जोड़ा जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं को एनआईओएस द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

जिले में वित्तीय गतिविधियों को गति देने हुई डीएलसीसी और डीएलआरसी की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में विकासोन्मुख वित्तीय गतिविधियों को गति देने और बैंकों तथा सरकारी विभागों के

बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से डीएलसीसी, डीएलआरसी की तिमाही बैठक शुक्रवार को यहां जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एस.जयवर्धन द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले, आरबीआई एजीएम दिपेश तिवारी, डीडीएम अनुपम तिवारी, एलडीएम आनंद प्रकाश मिंज विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। योजना से अधिक से अधिक संख्या में जिलेवासी जुड़े इस हेतु उन्होने बैंकर्स को आवश्यक सहयोग करने की अपील की। उन्होने कहा योजना के लक्ष्य को पूरा करने में बैंकर्स संबंधित विभाग और वेंडर्स से बेहतर समन्वय स्थापित करें। योजना से जुड़ने के इच्छुक हितग्राहियों के लिए एक चेक लिस्ट निर्धारित करें ताकि हितग्राही उस चेक लिस्ट के आधार पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक से ऋण या लोन प्राप्त कर सकें। बैठक में जमा अग्रिम व ऋण जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना की प्रगति, स्वयं सहायता समूह को नगद ऋण सीमा की प्रगति, स्वयं सहायता समूह को प्रदाय मुद्रा ऋण की प्रगति, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति पर, पशुपालन और मत्स्यपालन हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति, व्यक्तिगत, समूह व बैंक लिनकेज प्रगति, अंत्योदय स्वरोजगार योजना की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रगति पर क्रमवार चर्चा की गई।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला—सरगुजा

रा०प्र०क्र०— / अ—6 / 2025 26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुराग राजेन्द्र कुमार शर्मा आ. राजेन्द्र कुमार शर्मा, उम्र—43 वर्ष, निवासी चन्दगी राम, रेसीडेन्सी मकान नं. 08. रानी सती मंदिर सत्तीपारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के द्वारा अनावेदक विष्णु प्रताप अग्रवाल कर्ता, H.U.F. आ.स्व चन्दगीराम अग्रवाल, उम्र— 75 वर्ष, निवासी सेठ बसंत लाल मार्ग, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं. 09 मोहल्ला बाबूपारा, मौलवी बांध नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि भूखण्ड क्र. 3467 / 4866 / 95 रकबा 43110 वर्गफीट में से रकबा 1016 वर्गफीट भूमि / मकान को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 13 / 01 / 2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने के आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 18 / 03 / 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दादा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26 / 02 / 2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला—सरगुजा

रा०प्र०क्र०— / अ—6 / 2025 26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण सैयद इकराम हुसैन आ.स्व. सैयद असीमुद्दीन, उम्र— 48 वर्ष, सैयद इरफान हुसैन आ.स्व. सैयद असीमुद्दीन, उम्र— 44 वर्ष, दोनों निवासी महाराजा होटल के पीछे, सिंधी कॉलोनी तह० अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा तदाशय का आावेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण सैयद साहदा परवनी पत्नि नूर आलम खान, वगैरह के संयुक्त खामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि नगर अम्बिकापुर स्थित शीट नं. 03 मोहल्ला महाराज होटल गली स्थित खसरा क्रमांक 1054 / 3 रकबा 0.12 1 / 2 एकड में से रकबा 0.07 एकड भूमि का पंजीबद्ध हकत्याम पंजीयन दिनांक 08 / 01 / 2026 का निष्पादन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है। अतः उका पंजीबंध हक त्याग विलेख के आधार पर उक्त नजूल भूमि के अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा पंजीबद्ध विलेख की छायाप्रति मथ दस्तोवज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। तो ये अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 18 / 03 / 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दादा / अपरित पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 26 / 02 / 2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

आमजन के हितों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : चन्द्रमणि

जिपं में हुई सामान्य सभा और प्रशासन समिति की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में सामान्य सभा एवं प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल रजवाड़े उपस्थित रहीं। बैठक में अध्यक्ष श्रीमती पैकरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे। उन्होंने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। इस बैठक में लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, जल संसाधन, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्स्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, सेतु मण्डल विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, विद्युत विभाग, क्रेडा विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्यान विभाग, मनरेगा विभाग, शिक्षा विभाग विभागों के अधिकारियों द्वारा संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई तथा आगामी कार्य योजनाओं से सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली गयी ।जलसंसाधन

,15वां वित्त विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र और खाद्य विभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था, सोलर आधारित जल प्रदाय योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत जल प्रदाय योजना सहित मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान उक्त विभाग की समीक्षा की दौरान सिंचाई योजनाओ पर चर्चा करते हुए जिले में जलाशयों की स्थिति, चेक डैम निर्माण की आवश्यकता, सिंचाई साधनों की जानकारी ली गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। पीएम श्री स्कूल और आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, लाभान्वित बच्चों तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा निर्माणाधीन स्कूल भवन को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के तहत धान, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन जैसी फसलों के पैदावार सम्बन्ध में जानकारी दी गई। साथ ही उर्वरक और बीज भंडारण और वितरण की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। पशु विभाग द्वारा कुकुट इकाई वितरण योजना, सुकर त्रई इकाई वितरण योजना, बकरा वितरण योजना, पशुधन मित्र योजना ,राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना इत्यादि अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। मोबाइल वेटनरी यूनिट, किसान क्रेडिट कार्ड और दुग्ध सहकारी समिति की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले के सभी अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं सहित जिले में रोपनी फसलों और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की प्रगति की जानकारी दी गई, वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं में एकलव्य आदर्श विद्यालय, छात्रावासों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। छात्रावासों का मरम्मत, छात्रावासों में रिक्त सीटों की जानकारी और छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा वन अधिकार पट्टा वितरण की जानकारी ली गई। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की स्थिति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों पर चर्चा हुई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मत्स्य बीज वितरण और सब्सिडी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले तथा सभी जिला पंचायत सदस्य एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नर्सिंग कॉलेज व महिला समृद्धि बाजार की स्थापना की मांग, दिशा की बैठक में सांसद को नगर पालिका अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिला पंचायत सभाकक्ष में अयोजित दिशा की बैठक में मौजूद सांसद चिंतामणि महाराज को बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े ने ज्ञापन सौंपकर जन अपेक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण मांगें रखीं है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सूरजपुर को जिला बने 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसके बावजूद जिलेवासियों की कई मूलभूत अपेक्षाएं अब भी अधूरी हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि जिले में निजी एवं शासकीय अस्पतालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में नर्सिंग कोर्स के प्रति युवाओं का रुझान भी तेजी से बढ़ा है। यदि जिला मुख्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होती है तो मेडिकल एवं नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला समृद्धि बाजार स्थापित करने की आवश्यकता भी उठाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से घरेलू उद्योगों के लिए प्रोत्साहित तो किया गया है, लेकिन उनके उत्पादों के विक्रय हेतु समुचित बाजार व्यवस्था नहीं है। महिला समृद्धि बाजार की स्थापना से महिला उद्यमियों को स्थायी मंच मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। ज्ञापन के अंत में सांसद से सहानुभूति पूर्वक विचार कर मांगों की स्वीकृति प्रदान कराने का आग्रह किया गया। सांसद ने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ संबंधित स्तर पर रखा जाएगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

शुद्धिपत्र-3

ई-निविदा सूचना संख्या: 100- एस एन टी- परियोजना-निविदा- 2026, दिनांक: 20.12.2025

शुद्धिपत्र- 3: उपरोक्त निविदा संख्या में शुद्धि पत्र- 3 **दिनांक 24.02.2026** को जारी किया गया है। निविदा खुलने के दिनांक में परिवर्तन किया गया है । **संशोधित दिनांक: 20.03.2026 को 12.00 बजे तक।**

विस्तृत जानकारी निविदा दस्तावेज का विक्रय, पात्रता का मापदंड तथा अन्य विस्तृत विवरण हेतु हमारी वेबसाइट https://www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है, उससे देख सकते हैं।

उप मुख्य सि. एवं दूर. इंजी.(परियोजना-II)
सीपीआर/10/724 द.पू.मध्य रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर